दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

7 | 3 ट्रेन के आगे खड़ी हो गईं दो सहेलियां | 5 63 दरोगाओं के तबादले | 8 पिनल पर होगी पदक दिलाने की जिम्मेदारी

UPHIN51019 | वर्षः 02, अंकः 06 | पृष्ठ संख्याः 8 | मूल्यः 1.00 रू. | सोमवार 05 अगस्त, 2024

बांग्लादेश में हजारों छात्र क्यों कर रहे प्रदर्शन, क्या हिंसा के पीछे पाकिस्तानी सेना–ISI का हाथ ?

बांग्लादेश के बुरे हालात

ढाका ,एजेंसी।

क्या बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है? बताया गया है कि बांग्लादेश में 'छात्र शिविर' नाम के छात्र संगठन ने हिंसा को भड़काने का काम किया है। यह छात्र संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमात–ए–इस्लामी की शाखा है। बताया जाता है कि जमात–ए–इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है।

बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांतिपूर्ण रूप से चल रहे छात्रों के प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर दिया? यह आंदोलन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ताधारी आवामी लीग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर देश छोड़ दिया है। उधर, प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को राजधानी ढाका में रैली करने की योजना तैयार की है। इससे पहले देश में हिंसा भड़कने से कई लोगों की मौत हो गई।

इस बीच बांग्लादेश में सेना ने कर्फ्यू लगाया है और अधिकारियों ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है।

प्रदर्शनकारियों–पुलिस के बीच झड़प में 300 लोगों की मौत

इससे पहले रविवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में करीब 300 लोग मारे गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिसंक झड़पें हुईं हैं। दरअसल, प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित की गईं हैं।

ऐसे भड़की दंगों की आग

प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि मौजूदा आरक्षण के नियमों का फायदा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े लोगों को मिल रहा है। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। सरकार ने बांग्लादेश में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद भी सरकार देश में फैली अशांति को नियंत्रित करने में विफल साबित हुई। उधर, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रदर्शनकारी नाखुश नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्वतंत्रता संग्रामियों परिजनों को सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला आरक्षण पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश की सेना के पूर्व प्रमुख इकबाल करीम ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस बीच मौजूदा सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और इस वजह से देश में दंगों की आग और भी अधिक भड़क गई।

क्या लहसा भड़कने के पीछे पाकिस्तान की आई एसआई का हाथ है ?

अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विस इंटेलीजेंस (आईएसआई) का हाथ है? बताया गया है कि बांग्लादेश में 'छात्र शिविर' नाम के छात्र संगठन ने हिंसा को भड़काने का काम किया है।

यह छात्र संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमात–ए–इस्लामी की शाखा है। बताया जाता है कि जमात–ए–इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। उधर, बांग्लादेश सरकार इस बात का पता कर रही है कि क्या मौजूदा स्थिति में आईएसआई ने भी हस्तक्षेप किया है।

आंसू, ढांढस और इंतजार

हिमाचल में भयंकर बाढ़ में बहे 36 लोगों का सुराग नहीं कोने–कोने में तलाश

शिमला। बादल फटने से बुधवार आधी रात को रामपुर बुशहर के समेज खड्ड में आई भयंकर बाढ़ में बहे 36 लोगों का दूसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। शुक्रवार तड़के पांच बजे से स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम, होमगार्ड, आईटीबीपी, बायल से आए भारतीय सेना के जवान बारिश में भी खड्ड के आसपास और मलबे में लापता लोगों को खोजते रहे पर शाम तक कोई कामयाबी नहीं मिली। वहीं लापता लोगों के परिजन और उनके रिश्तेदार भी अपने लोगों को तलाश करते रहे। दोपहर 12 बजे बारिश होने पर रेस्क्यू टीम को परेशानी हुई। इसके बावजूद टीम डटी रही। समेज में अभी तक 20 परिवारों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत राशि दी गई है। हर परिवार को 15–15 हजार रुपये दिए गए हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि पीड़ित और प्रभावितों दोनों को फौरी राहत राशि जारी कर दी है। एक अगस्त देर शाम को ही राशि वितरित कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्र गति से चला हुआ हैं। हमारा लक्ष्य हर लापता को ढूंढने का है। रेस्क्यू टीम में अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। बिजली और पानी की व्यवस्था को भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा। 85 किलोमीटर तक सर्च अभियान चला हुआ है। वहीं निरमंड प्रशासन की ओर से भी प्रभावितों को राहत राशि दी गई।

एमबीबीएस की 675 सीटों पर शुरू होगी पढ़ाई, एक साल में बढ़ीं 300 सीटें

गोरखपुर। जिस गोरखपुर मंडल में इलाज और चिकित्सा शिक्षा के लिए एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, बीते सात साल में योगी सरकार ने उसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन का हब बना दिया है। इस मंडल में इस साल एमबीबीएस की 300 नई सीटों पर दाखिला शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर मंडल में एमबीबीएस की 675 सीटों पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सरकार के प्रयास से इस मंडल में सात साल में एमबीबीएस की करीब सात गुना सीटें बढ़ गई हैं। सात साल पहले तक गोरखपुर को केंद्र मानकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के माथे पर बदहाली की पहचान चस्पा थी। गोरखपुर समेत आसपास के कई मंडलों, सीमाई बिहार और नेपाल तक के लोगों के इलाज के लिए उम्मीद की एकमात्र किरण बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर ही था। इस पूरे अंचल में एमबीबीएस की पढ़ाई का भी एकमात्र केंद्र यही था। अव्यवस्था के चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बीमार नजर आता था तो कई बार इसकी एमबीबीएस की मान्यता पर तलवार लटकती रही।

कभी एक मेडिकल कालेज था, आज हैं पांच

कभी एक मेडिकल कॉलेज वाले इस मंडल के चार जिलों में आज पांच मेडिकल कॉलेज हैं तो विश्व स्तरीय एम्स भी है। एक लंबे दौर तक यहां सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही एमबीबीएस की 100 सीटों पर पढ़ाई होती थी। इसमें 125 सीटों की वृद्धि गोरखपुर में एम्स खुलने के साथ तथा 100 सीटों का इजाफा देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा राज्य स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेज की स्थापना से हुआ। मंडल में इस साल से तीन नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 300 सीटों पर दाखिला और पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इनमें कुशीनगर में राज्य स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेज को 100, महराजगंज में पीपीपी मॉडल पर संचालित केएमसी मेडिकल कॉलेज को 150 और निजी क्षेत्र के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत संचालित श्रीगोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को एमबीबीएस की 50 सीटों के लिए मान्यता और लेटर ऑफ परमिशन नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से प्राप्त हुआ है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में बीएएमएस की 100 सीटों के लिए पहले से ही मान्यता प्राप्त है।

इस साल पूरा हो जाएगा आयुष विवि

गोरखपुर में इस साल के अंत तक राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। आयुष विश्वविद्यालय के पूर्णतः क्रियाशील होने के बाद आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी आदि चिकित्सा पद्धतियों से इलाज व इन पद्धतियों में शिक्षा का भी प्रसार और विस्तार होगा।

गोरखपुर मंडल में मेडिकल एजुकेशन की नवीनतम स्थिति

कॉलेज	एमबीबीएस सीट
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर	150
एम्स गोरखपुर	125
देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया	100
श्रीगोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर	50
राज्य स्वा. मेडिकल कॉलेज कुशीनगर	100
केएमसी मेडिकल कॉलेज महराजगंज	150

बंग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला

गोरखपुर। बंग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में एटीएस जांच कर रही है। टीम शाम को कुशीनगर पहुंची। तरयासुजान से सीएसपी संचालक और विशुनपुरा सीएचसी पर तैनात डाटा ऑपरेटर को साथ लेकर चली गई। रायबरेली के सलोन में बंग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जांच कर रही एटीएस देर शाम को कुशीनगर पहुंची। जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में जिले के स्वास्थ्य विभाग के आईडी पासवर्ड का भी प्रमाण पत्र बनाने में इस्तेमाल किया गया है। तरयासुजान से सीएसपी संचालक और विशुनपुरा सीएचसी पर तैनात डाटा ऑपरेटर को साथ लेकर चली गई।

जन्म प्रमाण पत्र बनाने में इस्तेमाल होने वाला लैपटॉप, मोबाइल व अन्य उपकरण कब्जे में ले लिया है। संजीव से एटीएस ने उसके घर पर एक घंटे तक पूछताछ की। दोनों को लेकर लखनऊ पहुंची एटीएस पूछताछ कर रही है। सूत्रों की मानें तो संविदा पर तैनात डाटा ऑपरेटर ने स्वास्थ्य विभाग का आईडी और पासवर्ड सीएचसी संचालक को दे रखा था, जिससे फर्जीवाड़ा किया गया है।

महराजगंज जिले के खुशहाल नगर निवासी सतीश सोनी संविदा पर विशुनपुरा सीएचसी पर डाटा ऑपरेटर के पद पर तैनात है। दो वर्ष पूर्व इसकी तैनाती तरयासुजान सीएचसी पर थी, जहां वह स्वास्थ्य विभाग की आईडी से जन्मप्रमाण पत्र बनाने के साथ इसे पोर्टल पर अपडेट करता था। सतीश ने तरयासुजान में रहते हुए यूजर आईडी और पासवर्ड को भावपुर के सीएससी संचालक संजीव सिंह को दे दिया था।

दोनों साथ मिलकर बांग्लादेशी नागरिकों के कुछ फर्जी प्रमाण पत्र बना दिए। रायबरेली के जीशान की ओर से किए गए फर्जीवाड़े की जांच में एटीएस ने पूछताछ की तो कई प्रदेश के सहज जन सेवा केंद्र संचालकों से तार जुड़ा। इसी कड़ी में एटीएस को कुशीनगर में भी कुछ फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर देने का सुराग हाथ लगा। शाम को सादे वर्दी में पहुंचे एटीएस के अधिकारियों ने सबसे पहले संजीव सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो सतीश सोनी का नाम सामने आया। इसके बाद टीम विशुनपुरा सीएचसी पर पहुंची।

पहले लिखित में दिया नहीं चाहते कार्रवाई... फिर की तोड़फोड़ और आगजनी, गांव बना छावनी

बरेली।बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के गांव चंदपुरा शिवनगर में युवती को जबरन साथ ले जाने के आरोपी युवक के घर में शुक्रवार की रात तोड़फोड़ और आगजनी की घटना करने वालों ने जब पुलिस पर ही हमला कर दिया तो पूरे गांव को छावनी बना दिया गया। इंस्पेक्टर के मुताबिक एक दिन पहले मामले की जानकारी हुई थी।

इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। युवती मिलने के बाद उसके परिजनों ने लिखकर दिया था कि वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इससे पुलिस को भी इतने बड़े बवाल की आशंका नहीं थी, लेकिन शुक्रवार की रात ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया। भीड़ देखकर उसके परिवार वाले जान बचाकर भाग गए। इसके बाद भीड़ ने युवक के मकान की चहारदीवारी ढहा दी। अंदर घुसकर रसोई और घर में ही संचालित परचून की दुकान में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। गुस्साए लोग यहीं नहीं थमे और पांच कमरों से सामान बाहर निकालकर पूरा मकान ही आग के हवाले कर दिया। तोड़फोड़ व आगजनी की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस नाकाफी साबित हुई। किसी तरह भीड़ से बचकर भागे पुलिसकर्मियों ने सिरौली थाने में जानकारी दी तो सिरौली के साथ ही आसपास के थानों की पुलिस वहां पहुंची। मगर तब तक हमलावर भाग चुके थे।

घटना की सूचना पर सबसे पहले डायल 112 की गाड़ी पहुंची। तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस कर्मियों ने समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। पुलिस पर भी हमलावर हो गए। किसी तरह पुलिस कर्मी गाड़ी समेत गांव से बाहर निकलकर भागे और थाना पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद भारी संख्या में पुलिसबल गांव पहुंचा।

सम्पादकीय

जनगणना से कब तक डरना

जनगणना का काम सिर्फ दूसरे सर्वेक्षणों का आधार बनना या उनकी पृष्ठभूमि तैयार करना नहीं है। उसका काम है देश की आबादी का, उसके आर्थिक, सामाजिक, भौतिक जीवन की वास्तविकता को सामने लाना। मकान की गिनती और स्थिति से शुरू होकर अब यह परिवार और व्यक्ति को लेकर बीसियों सूचनाएं जुटाता है और फिर उनको जमा करने के साथ वर्गीकृत करता है, विश्लेषित करता है। बजट से जुड़ा हलवा बांटने वाले और हलवा खाने के रुपक के सहारे बात को जातिगत जनगणना तक ले जाने वाले राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चल दी। अब इसका कितने लोगों पर कैसा असर हो रहा है इसका हिसाब अलग–अलग हो सकता है, लेकिन भाजपा पर इसका प्रभाव काफी पड़ा है। उसकी तरफ से राजनीति को हिन्दू–मुसलमान लाइन पर ले जाने का प्रयास बंद नहीं हुआ है लेकिन अब वह हर बात में जाति के सवाल को महत्व देने लगी है और राहुल गांधी तथा कांग्रेस को ही नहीं समाजवादी पार्टी और राजद को ही पिछड़ा और दलित विरोधी बताने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से वह जातिगत जनगणना के खिलाफ है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं मानती–भले उसने बिहार में हुई जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। लेकिन राहुल गांधी को अपनी इस राजनैतिक रणनीति या भाजपा की घेराबंदी में एक बार भी याद नहीं आया कि देश में वह सामान्य जनगणना भी नहीं हुई है जो विश्वयुद्ध के दौरान भी नहीं रुकी थी। और सरकार ने जिस कोरोना के नाम पर जनगणना रोकी थी (हालांकि दुनिया में ऐसा सिर्फ दो अन्य देशों में ही हुआ था) उसे गए जमाना हो गया है और अब आम चुनाव समेत सब काम रूटीन पर लौट आया है।

विपक्ष का नेता होने के चलते राहुल को यह पूछने की जरूरत थी क्योंकि इस बजट में भी जनगणना के लिए धन का प्रावधान नहीं हुआ है–यह रकम पहले से कम कर दी गई है। और तब भले गृहराज्य मंत्री ने सदन में और गृह मंत्री ने बाहर कोरोना के चलते जनगणना रोकने और ज्यादा व्यापक सवालों के साथ जनगणना कराने की बात कही हों अब तो सरकार के अधिकारी कहने लगे हैं कि 1948 के जनगणना कानून में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि हर दस साल पर अनिवार्य रूप से जनगणना हो ही। संभवतः ऐसा है भी लेकिन पिछले डेढ़ सौ साल की जनगणना की परंपरा और उसकी रोजाना के काम की उपयोगिता ने हमारे लिए कानून के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं छोड़ी थी। चुनाव के क्षेत्र निर्धारण से लेकर सरकारी नीतियां बनाने और संसाधनों के आवंटन तथा आगे होने वाले हर सर्वेक्षण में जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने की आदत हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह समा गई है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छे दिन लाने और देश को विकसित दुनिया की बराबरी पर लाने और विश्वगुरु बनाने के दावे करने वाली सरकार जनगणना रोक देगी। इस सरकार का आंकड़ों से 'बैर' अब छुपा नहीं है। उसने जाने कितने आंकड़े जुटाने का काम रोका है, कितने जुटे आंकड़ों को प्रकाशित नहीं होने दिया है, कितने ही दूसरे अनुमानों को झुठलाया है, जीडीपी की गणना से लेकर न जाने किस–किस हिसाब का आधार ही बदल दिया है। इन सबसे हमारे सारे आंकड़े संदेहास्पद हो गए हैं जबकि ब्रिटिश शासन काल से ही महा–सांख्यिकी लेखाकार के अधीन आंकड़े जमा करने की एक मजबूत व्यवस्था के अभी तक काम करते जाने के चलते दुनिया में हमारे आंकड़ों को बहुत सम्मान से देखा जाता था। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने जीएसटी कर वसूली के निरंतर बढ़ते जा रहे आंकड़ों और कर वसूली बढ़ने के आंकड़ों को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी। देश विदेश के विभिन्न संस्थानों द्वारा जैसे–जैसे जुटाए आंकड़े जब सरकार के पक्ष में होते हैं तो उनका शोर मचाया जाता है वरना उनको खारिज कर दिया जाता है। और बुनियादी दिक्कत यह है कि जब पंद्रह साल पुरानी जनगणना को रैंडम सैंपलिंग के लिए कितनी भी ईमानदरी से इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे गलत आने की पूरी गुंजाइश है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण हो या परिवार स्वास्थ्य या उपभोग सर्वेक्षण, सभी जनगणना के आंकड़ों को ही आधार बनाते हैं। जनगणना का काम सिर्फ दूसरे सर्वेक्षणों का आधार बनना या उनकी पृष्ठभूमि तैयार करना नहीं है। उसका काम है देश की आबादी का, उसके आर्थिक, सामाजिक, भौतिक जीवन की वास्तविकता को सामने लाना। मकान की गिनती और स्थिति से शुरू होकर अब यह परिवार और व्यक्ति को लेकर बीसियों सूचनाएं जुटाता है और फिर उनको जमा करने के साथ वर्गीकृत करता है, विश्लेषित करता है। और अगर अमित शाह की कुछ समय पहले कही बात अब भी सच है तो इस बार की जनगणना में कुछ और नई जानकारियां जुटाने का काम होना है। इनके आधार पर ग्राम पंचायत और शहर के वार्ड से लेकर पंचायत और नगरपालिका, विधान सभा और संसदीय क्षेत्र का आकार–प्रकार बदला और तय किया जाता है। इनके आधार पर शहरी घोषित हो गए गांव और कस्बे में सुविधाओं और कायदे–कानून में बदलाव होता है। जिन आंकड़ों के आधार पर सरकार और स्वशासी संस्थाओं के बजट का आवंटन होता है। कई जानकारों का अनुमान है कि जिन पैमानों पर सरकार 81.5 करोड़ लोगों को आज मुफ़्त राशन दे रही है अगर आबादी के नए हिसाब(अनुमान ही) को ध्यान में रखा जाए तो 93 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन मिलना चाहिए। अब राजनैतिक मजबूरी के चलते सरकार बिहार जैसे पिछड़े राज्य को जो धन दे रही है वह काम काफी पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इससे भी बड़ी बात संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन, समाज के विभिन्न जमातों में आबादी की वृद्धि की रफ्तार, गरीबी काम–ज्यादा होने का हिसाब, मकान–दूकान–वाहन–खेती–संपत्ति का हिसाब है। सरकार इसमें से कई का हिसाब सामने आने देना नहीं चाहती। इससे उसकी राजनीति कमजोर होगी(खासकर मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की रफ्तार की असलियत से), दक्षिण और उत्तर के राज्यों के बीच संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन और उनकी संख्या घटने–बढ़ने के सवाल पर उलझ जाएगी। इस बार की जनगणना रोकना राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और सीएए जैसे विवादास्पद प्रावधानों की उलझन के चलते हुआ है। इन दो कानूनी प्रावधानों की जो दुर्गति हुई है सब देख रहे है। कुछ दर्जन केस भी सामने नहीं आए हैं। नागरिकता के उलझे सवाल पर सरकारी नजरिए का दोष जाहिर हुआ है और राजनैतिक लाभ की जगह घाटा हो गया है। यह भी हुआ कि जैसे ही सरकार ने जनगणना के साथ जनसांख्यिकी रजिस्टर और नागरिकता रजिस्टर वाली बात उठाई अनेक राज्यों ने विरोध कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो एनआरसी वाली जानकारी भरने वाले जनगणाकारों का घेराव और धर–पकड़ का आह्वान कर दिया था। सरकार इससे भी डर गई। सरकार के डरने और जनगणना रोकने का तीसरा कारण जातिगत जनगणना की मांग हो सकती है। राहुल ने वह काम तो नेता विपक्ष बनाकर कर दिया है लेकिन जनगणना की मांग को छोड़ दिया।

सरकारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की उम्मीद करना भारतीयों ने अरसे से छोड़ दिया है

क्या सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस का सदस्य बनने की इजाजत मिलनी चाहिए?मोदी सरकार में बेरोजगारी के भयावह आंकड़े सरकारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की उम्मीद करना भारतीयों ने अरसे से छोड़ दिया है। वे मानकर चलते हैं कि यदि किसी शासकीय स्कूल की इमारतें हों या फिर अस्पताल भवन, सड़कें हों या पुल–पुलिया– वे लम्बे समय तक नहीं चलेंगी। फिर वह निर्माण चाहे केन्द्र सरकार की देखरेख में बना हो या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्मित हो। सरकारी भवनों को जर्जर होते देर नहीं लगती। कभी स्कूल में पढ़ाई करते बच्चों पर छत का प्लास्टर गिर जाता है तो कभी शाला भवन की दीवार ही ढह जाती है, कभी किसी सरकारी कार्यालय की सीढ़ियां टूटने लगती हैं तो कभी उनकी दीवारों पर उद्घाटन के पहले ही दरारें पड़ने लगती हैं। पुल–पुलियों के खम्भे टूटने लगते हैं तो सड़कें अल्प समय के इस्तेमाल करते ही फटने लगती हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आये हैं। बिहार में पुलों ने गिरने का रिकॉर्ड बना दिया है। कुछ ही दिनों में दर्जन भर से अधिक पुल गिर गये। कई हाईवे पर तो उद्घाटन के केवल महीने–दो महीने में ही बड़ी दरारें पड़ गईं। सीवरेज अलग कहर ढाते हैं। जहां–जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं उनमें और भी बुरा हाल है। बारिश ने इस महत्वाकांक्षी व बहुप्रचारित योजना की पोल खोल दी है। सड़कों से लेकर मैदानों पर पानी ऐसा भरता है कि वाहन उनमें गिरते हैं, लोग हाथ–पांव तुड़वा रहे हैं या अपने प्राण गंवा रहे हैं। नियोजन से लेकर क्रियान्वयन तक सारा कुछ ऐसा दोषपूर्ण होता है कि इन योजनाओं का फायदा कम नुकसान ही अधिक होता है। जान–माल की हानि तो होती ही है, जीवन ही अव्यवस्थित हो जाता है। तिस पर अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाये तो जीवन को नर्क बनने में देर नहीं लगती।

अक्सर यह भी आरोप लगते हैं कि, जिसमें बड़े पैमाने पर सच्चाई भी है, भ्रष्टाचार का बड़ा योगदान गुणवत्ता को गिराने में होता है। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है बल्कि यह सार्वभौमिक सत्य है कि शासकीय कार्य का अर्थ ही है अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की जेबों का भरना। निर्माण कार्यों की लागत का आकलन तो वास्तविकता के आधार पर होता है, उसी कीमत पर कामों का आवंटन भी होता है परन्तु जब निर्माण शुरू होता है तो पता चलता है कि लाभ का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जायेगा। इससे ठेकेदार या निर्माण एजेंसियां गुणवत्ता में समझौते करती हैं। निर्माण हो जाता है व उसे विभाग को सौंप दिया जाता है, उद्घाटन हो जाते हैं लेकिन उन निर्माणों की गुणवत्ता जल्दी ही दीवारों, छतों, फर्शों और अन्य जगहों पर से झांकती दिखलाई पड़ती है। इसी कार्य पद्धति के तहत बने पुल लोगों पर गिरते हैं और मासूमों की मौतें होती हैं। देश में सैकड़ों हादसे ऐसे होते हैं जिनके लिये यही घटिया निर्माण जिम्मेदार होता है परन्तु उससे भी बुरी बात होती है इस पर होने वाली सियासत। यह नया भारत है जहां पहले यह देखा जाता है कि जो भी हादसा हुआ है या निर्माण की खामियां उजागर होती है, तो वह किस राज्य का मामला है और वहां किसकी सरकार है। पहले न कोई ऐसी वारदात का बचाव करता था और न ही भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता थी। लेकिन अब एक ही तरह की अलग–अलग राज्यों में होने वाली घटनाएं तय करती हैं कि उनकी आलोचना की जाये या बचाव। भारतीय जनता पार्टी की यह देन कही जा सकती है जिसके पास ऐसा प्रचार तंत्र है जो यह याद दिलाता है कि यदि अभी पुल–पुलिया गिर रहे हैं, एयरपोर्ट में पानी भर रहा है, रेलवे स्टेशन की छतों से पानी चू रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था– कांग्रेस के समय। भाजपा की ट्रोल आर्मी को फर्क नहीं पड़ता कि जनता के पैसे से बने अयोध्या के राममंदिर की छत से चू रहे पानी से गर्भगृह लबालब हो रहा है या महाकालेश्वर में लगाई गयीं मूर्तियां गिर रही हैं। करोड़ों की लागत से बने एक्सप्रेस–वे टूट जायें या पुल ढह जायें– उनकी बला से।

अपने प्रचार तंत्र और समर्थकों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर नरेन्द्र मोदी को बहुत भरोसा है, फिर वे यह भी जानते हैं कि उन्हें इसे लेकर किसी को जवाब देना नहीं है। यही कारण है कि उनकी सीधी देखरेख में बने और उनका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नये संसद भवन में पानी टपकने को लेकर सरकार का कोई बयान नहीं आया है। वैसे ही जिस प्रकार कुछ हवाई अड्डों में पानी भरने व एक्सप्रेस–वे टूटने पर कुछ नहीं कहा गया। इसके बावजूद देश के सबसे प्रतिष्ठित भवन की छत से अपने निर्माण के इतने कम समय में पानी टपकने की जिम्मेदारी से मोदी नहीं बच सकते।

उन्होंने इसका निर्माण बहुत जल्दबाजी में कराया था। कोरोना काल में जब देश के लिये एक–एक रुपया महत्वपूर्ण था, इस पर करोड़ों रुपये लगाये गये (कितने, यह स्पष्ट नहीं)। मोदी इस काम का बार–बार निरीक्षण करते रहे। सेफ्टी हैलमेट लगाकर ड्राइंग फैलाये अन्य इंजीनियरों को जिस प्रकार से उंगली दिखाकर निर्देश देते हुए मोदी की तस्वीरें देश–दुनिया में प्रकाशित व प्रसारित हुई थीं, वैसी ही गुरुवार को सुबह से उस नीली बाल्टी की फोटुएं वायरल हो रही हैं जिसमें 'सेंट्रल विस्टा' कहे जाने वाले नवीन संसद भवन के भव्य गुंबद से टपकता पानी इकठ्ठा हो रहा है। निर्माण में स्पेस टेक्नालॉजी का इस्तेमाल का दावा करने वाले मोदी को इस पर कुछ कहना चाहिये क्योंकि पुराने संसद भवन के बरक्स उन्होंने इसे अधिक गौरवशाली माना है।

तेहरान में हमास नेता हनीयेह की हत्या से मध्य पूर्व में युद्ध भड़कने की संभावना

– नित्य चक्रवर्ती

हनियेह उग्रवादी समूह के निर्वासित राजनीतिक प्रमुख थे और उन्होंने हाल के वर्षों में अपना अधिकांश समय कतर और तुर्की में बिताया था। उन्हें एक व्यावहारिक व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने इज़राइल–गाजा युद्ध के दौरान युद्ध विराम वार्ता में एक वार्ताकार के रूप में काम किया था। उन्होंने हमास के मुख्य सहयोगी ईरान के साथ संपर्क किया था और तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उन्हें एक कुशल वार्ताकार के रूप में बहुत महत्व दिया जाता था ।

मध्य पूर्व में अभूतपूर्व उथल–पुथल मच गई, जब खबर आई कि तेहरान में सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने उनके आवास में हमास नेता इस्माइलहनीयेह की हत्या कर दी। हालांकि ईरानी सरकार ने कहा कि वे हत्या की जांच कर रहे हैं और इजरायली सरकार ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिलिस्तीन के नेताओं ने इसे 'विश्वासघाती ज़ायोनी छापा' करार दिया।

इससे पहले, ईरान के रिवोल्यूशनरीगार्ड्स ने कहा कि उन्हें एक ईरानी अंगरक्षक के साथ उनके आवास में निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति मसूदपेजेशकियन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए ईरान गये थे। पेजेशकियन को पिछले महीने राष्ट्रीय चुनावों में ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया था। 30 जुलाई को उनके शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम एशियाई देशों के कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया था।

हनियेह उग्रवादी समूह के निर्वासित राजनीतिक प्रमुख थे और उन्होंने हाल के वर्षों में अपना अधिकांश समय कतर और तुर्की में बिताया था। उन्हें एक व्यावहारिक व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने इज़राइल–गाजा युद्ध के दौरान युद्ध विराम वार्ता में एक वार्ताकार के रूप में काम किया था। उन्होंने हमास के मुख्य सहयोगी ईरान के साथ संपर्क किया था और तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उन्हें एक कुशल वार्ताकार के रूप में बहुत महत्व दिया जाता था और हमास नेतृत्व ने पिछले साल 7अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से इज़राइल के खिलाफ़ हमास की लड़ाई के लिए सहायता का आयोजन करने में उनके कौशल का उपयोग किया।

हनियेह को खालिदमेशाल की जगह लेने के लिए 2017 में हमास राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था, लेकिन वह पहले से ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, क्योंकि 2006 में उस वर्ष के संसदीय चुनाव में हमास की अप्रत्याशित जीत के बाद वे फ़िलिस्तीनी प्रधानमंत्री बन गये थे। तुर्की सरकार के साथ उनके अच्छे संबंध थे और उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगन से फिलिस्तीनी लड़ाकों के पक्ष में वित्तीय और अन्य सहायता का प्रबंध किया था। अब तक इजरायल के युद्ध में 39,400 फिलिस्तीनी मारे गये हैं और आधिकारिक तौर पर घायलों की संख्या 90,996 बताई गई है।

मारे गये हमास नेता गाजा में फिलिस्तीनियों और इजरायल के बीच संघर्ष विराम पर बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा थे, जिसकी निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे थे। पिछले सप्ताह वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों ने जल्द से जल्द संघर्ष विराम को अंतिम रूप देने के लिए कहा था। नेतन्याहू ने हमेशा की तरह देरी के लिए हमास नेतृत्व को दोषी ठहराया।

ताजा घटनाक्रम ने हमास नेतृत्व को नाराज कर दिया है और इस बात की पूरी संभावना है कि यह तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि लेबनान और तुर्की दोनों ही हमास का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने पिछले सप्ताह गोलनहाइट्स पर 12 लोगों की हत्या की थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। इसके जवाब में इजरायल ने मंगलवार को बेरूत पर हवाई हमला किया, जिसमें गोलनहाइट्स पर हमले के लिए जिम्मेदार हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर को निशाना बनाया गया।

इजरायल ने कहा कि पिछले सप्ताह के हमले के लिए लेबनान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेबनान स्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के अलावा, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि तुर्की फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजरायल में प्रवेश कर सकता है। अगर उनके शब्दों को कार्रवाई में बदला जाता है, तो यह वर्तमान युद्ध को एक नया आयाम देगा, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है और नाटो के अपने सदस्यों के लिए कुछ नियम हैं। पहले ही इजरायल ने नाटो के समक्ष विरोध जताया है कि तुर्की आतंकवादियों को वित्तीय धन पहुंचाने का एक जरिया है। अब भौतिक भागीदारी फिलिस्तीन–इजरायल युद्ध के क्षेत्रों का और विस्तार करेगी। अगले कुछ दिन मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण होंगे।

कोई कोना न रहे अछूता

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था से जुड़े एक मामले में गुरुवार को फैसला दिया कि राज्य सरकारें इन श्रेणियों में उपश्रेणियां बना सकती हैं ताकि इनमें ज्यादा पिछड़ी जातियों के लिए सब–कोटा निर्धारित किया जा सके। यह फैसला कई बिल्कुल अलग–अलग वजहों से अहम माना जा रहा है। संभावित असर पर नजर : यह इस सवाल से जुड़ा है कि SC/T के तहत आने वाले समूहों को एक समान माना जाना चाहिए या नहीं। 2004 में चर्चित ईवी चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की पीठ ने फैसला दिया था कि इन कैटिगरी में सब–कैटिगरी नहीं बनाई जा सकती। मगर सात सदस्यों की बेंच ने ताजा फैसले में इसे पलट दिया। चूंकि इस सवाल पर देश में अलग–अलग और काफी तीखी राय देखी जाती रही है, इसलिए फैसले के संभावित असर को लेकर कयासबाजी शुरू होना स्वाभाविक है।

सब तक लाभ पहुंचाने की भावना : सच यही है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था का फायदा भी SC/ST कैटिगरी के तहत आने वाली सभी जातियां समान रूप से नहीं उठा सकीं। ताजा फैसला इस सचाई को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों के लिए यह गुंजाइश बनाता है कि वे इस व्यवस्था का फायदा उन तबकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें जिन तक यह ठीक से नहीं पहुंचा है।

आशंकाओं पर अंकुश : अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने उन आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया, जो इस फैसले से जुड़ी हैं। फैसले में साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह का उप–वर्गीकरण स्पष्ट और भरोसेमंद डेटा के ही आधार पर किया जा सकता है। देखा जाए तो इस शर्त के जरिए फैसले का संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की संभावित कोशिशों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है।

जटिलता की झलक : यह फैसला इस लिहाज से भी याद रखा जाएगा कि मसले की जटिलता की झलक पीठ के सदस्यों की अलग–अलग राय में भी मिलती है। ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं कि 6:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में भी छह ओपिनियन सामने आएं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी तो बहुमत की राय से असंतुष्ट रहीं, लेकिन जो छह जज बहुमत की राय से सहमति रखते हैं, उनके भी पांच अलग–अलग फैसले आए। इनमें क्रीमी लेयर को SC/ST पर भी लागू करने और आरक्षण को एक पीढ़ी तक सीमित करने जैसे अलग–अलग तरह के कई सुझाव दर्ज हुए।

भविष्य के लिए दिशासूचक : साफ है कि कानून के लिहाज से बहुमत का फैसला ही मान्य होगा, लेकिन पीठ के सदस्यों के वैयक्तिक फैसलों में जाहिर हुए ये सुझाव आगे विमर्श की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर, फैसला न सिर्फ पॉलिसी के लेवल पर महत्वपूर्ण दखल है बल्कि आरक्षण जैसे मसले पर भविष्य के लिए दिशासूचक का भी काम कर सकता है।

कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

11 गवाह, 60 से ज्यादा तारीखें..

पत्नी की हत्या कर सिर लेकर घूमने वाले पति

संवाददाता, बांदा। अवैध संबंधों के शक में पत्नी का फरसे से सिर काटने के बाद उसका सिर पकड़कर पैदल थाने जाने वाले पति को जिला सत्र न्यायाधीश डा.बब्बू सारंग की अदालत ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मृत्युदंड के साथ उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए थे। उक्त प्रकरण में पांच जज बदले थे जब कि 60 से ज्यादा तारीखें पड़ी थीं। पौने चार साल बाद प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाया है।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नौ अक्टूबर 2020 को अवैध संबंध होने की शंका पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके सिर को काटकर पैदल थाने चला गया। अब जिला सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग की अदालत ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मृत्युदंड के साथ उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अवैध संबंध के शक में की थी हत्या

वर्ष 2020 में नौ अक्टूबर को बिसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम अमलोहरा के रहने वाले 39 वर्षीय किन्नर यादव ने पत्नी विमला के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने की शंका पर कोतवाली बबेरू के कस्बा नेता नगर में उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी। कथित प्रेमी पर भी उसने हमला किया था जिसमें उसने भागकर खुद को बचाया था। इसके बाद पत्नी का कटा सिर पकड़कर पति किन्नर कस्बे में पैदल घूमते हुए कोतवाली पहुंचा था। जहां उसने कहा था साहब इसे मैनें मार डाला। पुलिस व कस्बेवासी उसका यह रूप देखकर सन्न रह गए थे। बाद में दिवंगत पत्नी के पिता रामसरन यादव की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जयश्याम शुक्ला ने की थी । विवेचक ने प्रभावी विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन कर 27 अक्टूबर 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था । लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर सिंह की ओर से जिला सत्र न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई । जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने हत्यारे पति को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

रेस्टोरेंट की कोल्ड काफी में मिले कीड़े

नोटिस– बिना पंजीकरण के ही चल था 'कोहिनूर'

गोरखपुर,संवाददाता। गोरखपुर के सिविल लाइंस स्थित कोहिनूर रेस्टोरेंट में कोल्ड कॉफी में कीड़े की मिलने शिकायत खाद्य विभाग से की गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेन मोहन त्रिपाठी के निर्देश पर विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट की जांच की। टीम ने पनीर और दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। रेस्टोरेंट संचालक के पास फूड लाइसेंस नहीं था। इसके लिए संचालक को नोटिस दिया गया है। टीम ने रिपोर्ट तैयार मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सौंप दी है। रेस्टोरेंट में कॉफी पीने गए एक व्यक्ति ने फोन करके मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी से शिकायत की थी कि जो कॉफी उन्हें दी गई उसमें कीड़े थे। इसकी वीडियो भी भेजी गई। जांच में गई टीम को साफ–सफाई भी ठीक नहीं मिली। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने प्रतिष्ठान के किचन से लेकर पूरे रेस्टोरेंट की जांच की। जांच के दौरान साफ–सफाई रखने का निर्देश दिया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कोहिनूर रेस्टोरेंट पर कोल्ड कॉफी में कीड़े पाए जाने की शिकायत पर टीम वहां पहुंची थी। जांच के बाद साफ सफाई के लिए नोटिस दिया गया है। प्रतिष्ठान का संचालन कर रहे मालिक के पास दूसरे का फूड लाइसेंस था। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आशुतोष कुमार, प्रतिमा उपाध्याय, कमल नारायण, संतोष तिवारी उपस्थित रहे।

एंटी करप्शन टीम ने पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा

गोरखपुर। एंटी करप्शन की टीम ने बुधवार को भूमि विवाद के मामले में समझौता कराने के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एक दीवान व सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। दोनों खोराबार थाने के रामनगर कड़जहां पुलिस चौकी पर तैनात थे। एंटी करप्शन की टीम ने उनके विरुद्ध कैंट थाने में भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराया है। एंटी करप्शन की टीम ने बुधवार को भूमि विवाद के मामले में समझौता कराने के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एक दीवान व सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। दोनों खोराबार थाने के रामनगर कड़जहां पुलिस चौकी पर तैनात थे। एंटी करप्शन की टीम ने उनके विरुद्ध कैंट थाने में भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराया है।

पकड़े गए दीवान की पहचान गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर अटवा निवासी एनाम खान के रूप में हुई है। सिपाही सूरज सिंह बलिया जिले के फेकना थाना क्षेत्र के लेवरुआ गांव का रहने वाला है। दोनों का इसी मामले में लोगों से विवाद करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। जानकारी के मुताबिक, कड़जहां गांव के रहने वाले दीनानाथ ने भूमि विवाद के संबंध में खोराबार के रामनगर कड़जहां पुलिस चौकी पर 10 दिन पहले शिकायत की थी। इसकी जांच चौकी पर तैनात दीवान एनाम खान और सिपाही सूरज सिंह कर रहे थे। समझौता करने के नाम पर दोनों 10 हजार रुपये रिश्वत मांग रहे थे।

पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस लाइंस स्थित एंटी करप्शन थाना प्रभारी से की। प्रभारी ने मामले की जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। बुधवार दोपहर एंटी करप्शन के निरीक्षक सुबोध कुमार के साथ दीनानाथ मोतीराम अड्डा चौराहे पर पहुंचा और रुपये देने के लिए उसने दीवान और सिपाही को फोन कर चाय की दुकान पर बुलाया। 15 मिनट बाद दीवान एनाम खान और सिपाही सूरज सिंह दुकान पर पहुंचे।

चाय पीने के दौरान जैसे ही दीनानाथ ने उन्हें रुपये दिए, एंटी करप्शन की टीम ने दबोच लिया। दीवान और सिपाही के पकड़े जाने की जानकारी थाना प्रभारी खोराबार के साथ ही एसएसपी को देने के बाद टीम उन्हें कैंट थाने ले आई, जहां पूछताछ करने के साथ ही केस दर्ज कर कराया गया। दोनों को निलंबित भी कर दिया गया है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एंटी करप्शन की टीम ने दीवान और सिपाही को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों पर कैंट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ट्रेन के आगे खड़ी हो गईं दो सहेलियां

हार्न बजाता रहा चालक, नहीं हटी, हुई दर्दनाक मौत

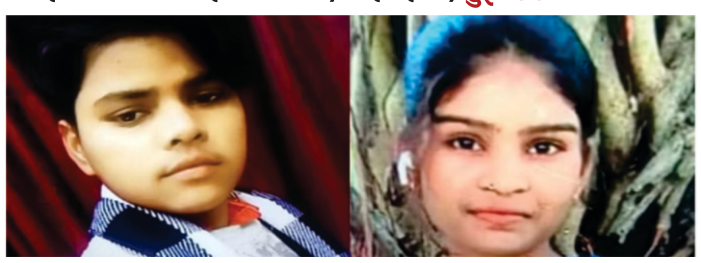

अलीगढ़,संवाददाता। तनु बीएससी जबकि खुशबू एलएलबी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। दोनों सहेलियां बताई जा रही हैं। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ते की बात भी सामने आ रही है। 31 जुलाई की देर शाम थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के दाऊद खान एवं न्यू दाऊद खान रेलवे स्टेशन के मध्य दिल्ली–रांची राजधानी एक्सप्रेस के सामने एलएलबी वह बीएससी प्रथम वर्ष की दो छात्राएं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़ी हो गईं। चालक हॉर्न बजाता रहा लेकिन वह ट्रैक से नहीं हटीं। ट्रेन से कटकर दोनों की मौत हो गई। शव भी टुकड़ों में बट गए थे। हादसे के बाद ट्रेन 35 मिनट तक खड़ी रही।

रात करीब नौ बजे इनकी पहचान थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के कोंछोड़ निवासी सुल्तान सिंह कुशवाहा की 20 वर्षीय बेटी तनु व गांधी पार्क के नगला माली के ज्ञान बाबू उर्फ ज्ञानवीर की 22 वर्षीय पुत्री खुशबू के रूप में हुई। तनु बीएससी जबकि खुशबू एलएलबी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। दोनों सहेलियां बताई जा रही हैं। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ते की बात भी सामने आ रही है। परिजनों के अनुसार दोनों 31 जुलाई की सुबह से ही साथ थीं, अब वह घर से इतनी दूर रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंची इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं है। उन्हें जो बताया गया है उसके मुताबिक शाम करीब छह बजे खंबा संख्या 1318–10 के मध्य गांव हाजीपुर के सामने दाऊद खान एवं न्यू दाऊद खान रेलवे स्टेशन के मध्य दिल्ली से रांची जा रही राजधानी एक्सप्रेस से कटकर दोनों की मौत हुई है। यह हादसा है या आत्महत्या इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता।

अब दिवंगतों के मान-सम्मान पर भी चलने लगा बाबा का बुलडोजर...

गोरखपुर,संवाददाता। गोरखपुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनकी प्रतिमा लगाने के लिए बन रहे चबूतरे को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान और मकान पर चलता था, लेकिन अब दिवंगतों के मान–सम्मान पर भी बुलडोजर चलने लगा है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव टाड़ा में उनकी प्रतिमा लगाने के लिए बनाए जा रहे चबूतरे को बुधवार दोपहर में प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। इस कार्रवाई पर हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर ने नाराजगी व्यक्त की है। उधर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि अब तक भाजपा का बुलडोजर मकान–दुकान पर चलता था, लेकिन अब यह दिवंगतों के मान–सम्मान पर भी चलने लग गया है।

एसडीएम गोला के नेतृत्व में कार्रवाई करने गई टीम को ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ा। काफी देर तक प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक होती रही। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक भूमि पर प्रतिमा लगाई जा रही थी। ग्राम प्रधान दयाशंकर तिवारी की मानें तो ग्राम पंचायत ने उस स्थान पर प्रतिमा लगाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। इसी बीच 21 जुलाई को टांडा गांव के डॉ. राजा वशिष्ठ त्रिपाठी ने उपजिलाधिकारी गोला को पत्रक देकर सार्वजनिक भूमि पर प्रतिमा स्थापना करने पर विरोध जताया। उन्होंने पत्र की कॉपी मुख्य सचिव, कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ गोला के साथ प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज को भी भेजी थी।

यह राजनीतिक अराजकता है : विनय शंकर

पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने कहा कि यह राजनीतिक अराजकता और प्रशासनिक ज्यादती है। यह सत्ता के अहंकार की निकृष्ट पराकाष्ठा है। व्यक्तिगत शत्रुता के चलते ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। इसका निर्णय समय आने पर चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश के लोग करेंगे। अपने सहयोगियों, समर्थकों से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए विनय शंकर तिवारी ने कहा कि इस अनीति का उत्तर जरूर दिया जाएगा, लेकिन कानून–व्यवस्था और मर्यादा की परिधि में रहकर।

अखिलेश ने कसा तंज

अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा अब तक भाजपा का बुलडोज़र दुकान–मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान–सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लूपार के सात बार विधायक रहे उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़वा देना, बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके।

निंदनीय!

जिन्दा शख्स को बता दिया मुर्दा, फिर जिला अस्पताल में मचा हंगामा

स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह मामले को संभाला। दरअसल, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती बक्शीपुर चौरहिया गोला निवासी सरजू (65) की मौत की सूचना वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने मोहल्ले वालों को देकर उन्हें मोर्चरी में पंचनामा भरने के लिए बुला लिया। करीब दो घंटे मोहल्ले वालों ने मोर्चरी और कोतवाली थाने की दौड़–धूप कर पंचनामा भरा। मोर्चरी से जब शव बाहर निकाला गया तो पता चला कि वह सरजू का नहीं है। परिजनों ने वार्ड में जाकर देखा तो सरजू अपने बेड पर लेटे थे।बताया जा रहा है कि एक सप्ताह में सरजू की मौत की झूठी सूचना दूसरी बार स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से दी गई है।

गोरखपुर । जिला अस्पताल में बुधवार को अजग–गजब का मामला सामने आया। यहां के सिस्टम ने बुजुर्ग सरजू को एक सप्ताह के भीतर कागज में दो बार मार डाला, बुधवार को तो पंचनामा भी भरवा दिया। वह तो भला हो परिजनों और मोहल्ले वालों की, कि उन्होंने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी।

वार्ड में बुजुर्ग सरजू जिंदा मिले तो मौके पर हंगामा होने लगा। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह मामले को संभाला। दरअसल, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती बक्शीपुर चौरहिया गोला निवासी सरजू (65) की मौत की सूचना वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने मोहल्ले वालों को देकर उन्हें मोर्चरी में पंचनामा भरने के लिए बुला लिया। करीब दो घंटे मोहल्ले वालों ने मोर्चरी और कोतवाली थाने की दौड़–धूप कर पंचनामा भरा। मोर्चरी से जब शव बाहर निकाला गया तो पता चला कि वह सरजू का नहीं है। परिजनों ने वार्ड में जाकर देखा तो सरजू अपने बेड पर लेटे थे।बताया जा रहा है कि एक सप्ताह में सरजू की मौत की झूठी सूचना दूसरी बार स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से दी गई है। बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने मौत होने का मेमो भी जारी कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा। जानकारी के अनुसार, चौरहिया गोला निवासी सरजू एक मिनारा मस्जिद के पास रहते हैं। बुजुर्ग होने की वजह से उनका दिमाग भी थोड़ा कमजोर हो गया है। 24 जुलाई को उल्टी–दस्त होने पर मोहल्लेवालों ने उन्हें जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था। मोहल्ले के ही आमिर के पास जिला अस्पताल से कॉल आया कि सरजू की मौत हो गई है। उनका मेमो कोतवाली थाने भेज दिया गया है। आकर पंचनामा भर दें, ताकि पोस्टमार्टम कराया जा सके।

दिखाए गए दो शव

मोहल्लेवासी करीब दो घंटे तक कोतवाली थाने और मोर्चरी का चक्कर लगाते रहे। पोस्टमार्टम के लिए शव निकाला गया तो उसका चेहरा देखकर लोगों ने बताया कि यह सरजू नहीं हैं। इसके बाद मोर्चरी से दूसरा शव निकालकर दिखाया गया। वह भी सरजू का नहीं था। मोहल्ले वालों ने काफी देर तक इमरजेंसी वार्ड में हंगामा किया। स्वास्थ्य कर्मियों के माफी मांगने पर वे शांत हुए। वहीं कोतवाली से आए पुलिस कर्मियों ने जो पंचनामा भरवाया था, उसे जल्दी–जल्दी फाड़कर फेंका गया।

मौत की सूचना पर पहुंची बहन

बताया जा रहा है कि चौरहिया गोला में सरजू अकेले रहते हैं। मौत की सूचना पर उनकी बहन आमना मायके से जिला अस्पताल पहुंचीं। वहां भाई को जिंदा देख वह चौंक गईं। अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि सरजू को अज्ञात में भर्ती कराया गया था। उनके बगल में ही घोष कंपनी का एक अज्ञात व्यक्ति भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह उसकी मौत हुई थी। गलती से सरजू का मेमो तैयार कर दिया था। जांच में पता चला है कि सरजू को खून की भी कमी है।

सुप्रीटेंडेंट जिला अस्पताल डॉ वीके सुमन ने बताया कि मैं लखनऊ ट्रेनिंग में आया हूं। इसका पता करवाता हूं। यह बड़ी चूक है। इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लापरवाही हुई है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

उफान पर सोलानी नदी, छह गांव के रास्तों पर पानी ही पानी

उत्तराखंड में बारिश और पानी छोड़ने से बढ़ी परेशानी

मुजफ्फरनगर। उत्तराखंड में बारिश से खादर क्षेत्र के छह गांव के रास्तों और जंगल में पानी भरा है। ग्रामीणों के सामने आवागमन और चारे का संकट खड़ा होने लगा है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया है। उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियों से आ रहे पानी के कारण सोलानी नदी उफान पर है। पानी नदी से बाहर निकलकर गांवों के रास्तों पर भर गया है। खादर क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पानी घरों के अंदर तक घुस जाने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। खेतों में पानी भर जाने से धान, गन्ने और ज्वार की फसलें बर्बाद हो गई हैं।

ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाव में बैठकर नदी पार करने को मजबूर हैं। गांव भदोला, पांचली, मारकपुर, रामनगर, रजगल्लापुर, शेरपुर नंगला समेत छह से अधिक गांव में संकट बढ़ा है।

पानी और बढ़ जाने से पानी गांव रामनगर, रजगल्लापुर, शेरपुर नगला, रतन पुरी के कई घरों में घुस गया, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया और ग्रामीण घरों में कैद होकर रह गए। लेखपाल प्रदीप सैनी का कहना है कि शनिवार तक पानी कम होने की संभावना है। गांवों को अलर्ट किया गया है।

क्या कहते हैं ग्रामीण

सरदार देवेंद्र खालसा, कुलवंत सिंह, जोगेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, जसविंदर सिंह, राजू प्रजापति, राजेंद्र पांचली, यादराम प्रजापति, गुलशन कुमार ने बताया कि खेतों में करीब करीब पांच फीट पानी भर गया है। गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। चारे की फसल बर्बाद हो जाने से पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या आ गई है। हरा चारा नहीं मिलने से पशुओं को भूसा खिलाना पड़ रहा है ।

मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या

ग्रामीण बताते हैं कि रोजाना मजदूरी कर घर चलाने वाले लोग अधिक परेशान हैं। वह मजदूरी पर नहीं जा पा रहे हैं। उनके समक्ष परिवार के पालन पोषण की समस्या खड़ी हो गई है।

पहाड़ियों से आता है पानी

सिंचाई विभाग के जेई अनिल कुमार ने बताया कि शिवालिक की पहाड़ियों से पानी नदी में आता है। शुक्रवार को बारिश बंद हो जाने से पानी बंद हो गया है। शनिवार तक खादर क्षेत्र में पानी का स्तर कम हो जाएगा।

पानी आते ही इन गांव में बढ़ता है खतरा

पुरकाजी खादर क्षेत्र के बढ़ीवाला भैंसली, आयकी, उदियावाली, रतनपुरी, रामनगर, रजकल्लारपुर, शेरपुर, शेरपुर नंगला, चानचक, चमरावाला बड़ा, जिंदावाला, खेड़की, हुसैनपुर, धुमनपुरी दादूपुर, भदौला फार्म, फरकपुर, पांचली और मारकपुर में खतरा बढ़ जाता है। इन गांवों में करीब 12 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

ये कालेज है... मदरसा नहीं, दाढ़ी कटाओ, यहां ऐसे नहीं पढ़ सकते, प्रधानाचार्य ने छात्र को कालेज से निकाला

बरेली। बरेली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां दाढ़ी रखकर इंटर कॉलेज पढ़ने आए छात्र को प्रधानाचार्य ने स्कूल से निकाल दिया। 31 जुलाई को प्रधानाचार्य ने छात्र से कहा था कि यह कॉलेज है, मदरसा नहीं, यहां ऐसे नहीं पढ़ सकते। बरेली से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सेंथल में दाढ़ी रखकर इंटर कॉलेज पढ़ने आए छात्र को बाहर निकालने का मामला साममे आया है। छात्र के बड़े भाई ने मामले में मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से की शिकायत है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

मोहल्ला नई बस्ती निवासी जीशान अली ने बताया कि उनका छोटा भाई फरमान अली एक इंटर कॉलेज में कक्षा नौवीं का छात्र है। आरोप है कि प्रधानाचार्य छात्र पर पिछले एक माह से दाढ़ी कटवाने का दबाव बना रहे हैं। न काटने पर कॉलेज से नाम काटने और कक्षा में फेल करने की धमकी भी दे रहे हैं।

जीशान ने बताया कि फरमान 31 जुलाई को कॉलेज गया तो प्रधानाचार्य ने उसे कक्षा में बैठने से मना कर दिया। दाढ़ी रखकर इंटर कॉलेज आए छात्र से प्रधानाचार्य बोले कि यह कॉलेज है, मदरसा नहीं। दाढ़ी कटाओ, यहां ऐसे नहीं पढ़ सकते। इतना कहते हुए प्रधानाचार्य ने उसे बाहर निकाल दिया।

साथ ही दाढ़ी के साथ कॉलेज में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में छात्र के भाई ने जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

शासन का आदेश नहीं दिखा सके

छात्र ने इसकी जानकारी घर आकर भाई को दी तो वह उसको लेकर कॉलेज गए तो प्रधानाचार्य ने दो टूक कहा कि यह मदरसा नहीं, कॉलेज है। यहां दाढ़ी रखकर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते। दाढ़ी कटवानी होगी, यही शासन का आदेश है। नहीं कटाई तो नाम काट दिया जाएगा। जब छात्र के भाई जीशान ने प्रधानाचार्य से शासन का आदेश दिखाने को कहा तो प्रधानाचार्य ने दोनों को कॉलेज से बाहर कर दिया।

एडमिशन के दौरान ही दे दी गई थी जानकारी: प्रधानाचार्य

नया एडमिशन है। छात्र से तब ही कह दिया गया था कि यूनिफॉर्म और अनुशासन में रहना है, लेकिन वह यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा था।

मामला मेरी संज्ञान में नहीं है। शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।–देवकी सिंह, डीआईओएस

योगी सरकार का दावा

भीतयों में ओबीसी को मिला सबसे ज्यादा लाभ

शिक्षक भर्ती में 31000 युवाओं का हुआ चयन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार, ओबीसी युवाओं को न केवल आरक्षण का लाभ मिला बल्कि मेरिट पर अनारक्षित पदों पर भी चयन हुआ। 69000 शिक्षक भर्ती में 31000 से अधिक ओबीसी युवाओं को सफलता मिली। योगी सरकार में होने वाली भर्तियों में ओबीसी युवाओं के साथ भेदभाव को लेकर जारी राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप के इतर आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। शासन के अनुसार, 2017 से अब तक प्रदेश में हुई भर्तियों में न केवल आरक्षण प्रावधानों का पालन हुआ, बल्कि कई में तो सामान्य वर्ग से ज्यादा चयन ओबीसी अभ्यर्थियों का ही हुआ है।

परिषदीय विद्यालयों में हुई 69000 शिक्षक भर्ती प्रकिया में अन्य पिछड़ा वर्ग के 18000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी। इसके सापेक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के 31000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसमें 18,598 ओबीसी कोटे में तथा 12,630 ओबीसी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए। ऐसा ही अनुसूचित जाति संवर्ग में भी हुआ है। शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 14000 से अधिक पद आरक्षित थे। इन सभी पदों पर तो एससी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ ही, नियमों के अनुरूप मेरिट के आधार पर 1600 से अधिक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी चयनित हुए। वहीं बचे 1100 से अधिक अनुसूचित जनजाति के खाली पदों को भी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा गया। इस तरह अनुसूचित जाति संवर्ग के कुल 17000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पद पर हुआ। संबंधित चयन परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के 34000 से अधिक पदों में 20,301 सामान्य श्रेणी, 12,630 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1,637 अनुसूचित जाति, 21 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन हुआ।

यूपीपीएससी में सबसे ज्यादा सफलता ओबीसी को

विधानमंडल के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का विधिवत पालन होने की बात सदन में रखी थी। उन्होंने लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के आंकड़े प्रस्तुत किए और सपा शासनकाल और मौजूदा समय में ओबीसी छात्रों को मिली सफलता के अंतर को समझाया था। उन्होंने कहा था कि सपा खुद को पीडीए के हितों की संरक्षक भले ही बताती हो, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि 2012 से 2017 के बीच सपा शासनकाल में लोकसेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर कुल 26,394 युवाओं का चयन हुआ था। अंतिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों में ओबीसी वर्ग की कुल हिस्सेदारी मात्र 26.38 फीसदी रही, जबकि एससी संवर्ग के युवाओं को 21.34 फीसदी सीटें मिली थीं। वहीं उनकी सरकार में 2017 से अब तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 46,675 भर्तियां हुई हैं, जिसमें 38.41 फीसदी अकेले ओबीसी संवर्ग के युवाओं का चयन हुआ है। वहीं 3.74 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को मिलीं। अनारक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के 36.76 फीसदी युवाओं को सफलता मिली।

आउटसोङ्गसग भूतयों में आरक्षण नहल, फिर भी ओबीसी युवाओं की हिस्सेदारी

सूचना विभाग में 676 में से 512 आरक्षित वर्ग के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। इसमें से 340 सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। यह संख्या 75 फीसदी के आसपास है। यह हाल तब है जबकि अभी आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं है। आउटसोर्सिंग कार्मिकों की नियुक्ति शासन स्तर पर नहीं बल्कि विभाग स्तर पर उसके द्वारा अधिकृत आउटसोर्सिंग एजेंसी करती है।

लखनऊ। प्रदेश में नजूल की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल चल रहा है। लगभग दो लाख करोड़ रुपये की इन सरकारी जमीनों को सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराने की जद्दोजहद की जा रही है।

इन जमीनों को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए लाया गया प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति– 2024 विधेयक विधानस परिषद में अटक गया है। आवास विकास फर्जी दस्तावेजों से फ्री होल्ड कराने वाली जमीनों को निस्तारित करेगा। नजूल की जमीन को फ्रीहोल्ड कराने के इस फर्जीवाड़े में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है।

यूपी में लगभग 25 हजार हेक्टेयर जमीन नजूल की है। विभाग के मुताबिक अब तक कम से कम 4 हजार एकड़ जमीन फ्री होल्ड कराई जा चुकी है। अब नजूल जमीनों के मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं।

करीब 2500 केस लाइन में हैं।

इनसे जुड़ी जमीनों की कीमत लगभग दो लाख करोड़ रुपये है। ये जमीनें सबसे ज्यादा प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी आदि में हैं। नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराने का केंद्र प्रयागराज है। यहां लगभग पूरा सिविल लाइंस नजूल की जमीन पर है। एक–एक बंगला 100 से 250 करोड़ रुपये का है।

100 करोड़ की जमीन केवल 5 करोड़ में फ्रीहोल्ड

सर्किल रेट के हिसाब से नजूल की किसी जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये है। उस जमीन का बाजार भाव 100 करोड़ है। इसे सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराया जा रहा है। यानि वह व्यक्ति केवल पांच करोड़ रुपये में 100 करोड़ रुपये की जमीन का मालिक बन जाता है।

खास बात यह है कि नजूल एक्ट में फ्री होल्ड का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन अब तक कम से कम 25 फीसदी नजूल की जमीन को इस तरीके से फ्री होल्ड कराया जा चुका है।

नजूल की जमीन क्या है

अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लगान चुका पाने में विफल लोगों की जमीनों को छीन लिया था। इसके बाद 1895 में गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट के तहत ये जमीनें मामूली किराये पर अंग्रेजों ने लीज पर दे दीं। इनकी लीज अवधि 90 वर्ष तक थी। इन जमीनों पर सरकार का मालिकाना हक है। ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड से रोकने के लिए प्रदेश सरकार नजूल एक्ट लाई है।

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक की खास बातें

सरकार इस एक्ट के जरिए नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने के खेल पर रोक लगाना चाहती है। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक नजूल की जमीनों पर जो लोग रह रहे हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा।

गरीब और कमजोर लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें हटाया भी नहीं जाएगा। केवल बची जगह पर पार्किंग, पार्क, सरकारी संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, पीएम आवास योजना या अन्य सार्वजनिक उपयोग में लाने का प्रावधान है। जमीन पर बसे बाजारों को बेहतर बनाने का प्रावधान है। नजूल एक्ट को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की राय से तैयार किया गया है।

संसद में सतीश गौतम का एएमयू पर हमला: विवि के मेडिकल में जाने से कतराते हैं हिन्दू परिवार

अलीगढ़। अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने संसद में एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां हिंदू मरीज जाने से कतराते हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्या प्रो. वीणा माहेश्वरी ने कहा कि यहां पर सभी धर्मों के मरीज आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने रुख को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सांसद सतीश गौतम ने संसद में एएमयू पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बेशक अलीगढ़ में केंद्रशासित मुस्लिम विश्वविद्यालय है और उसका ट्रॉमा सेंटर भाजपा शासन में विकसित हुआ है। मगर वहां समुदाय विशेष के डॉक्टरों की संख्या अधिक होने के कारण हिंदू परिवार इलाज के लिए जाने से कतराते हैं। इसलिए अलीगढ़ के ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय (डीडीयू) को एम्स की तरह विकसित किया जाए। संसद में अभिवादन भाषण के लिए सांसद सतीश गौतम को बोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद देता हूं। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर दिया गया। वह बनकर तैयार हो गया। बेशक यह केंद्रशासित है, मगर यहां समुदाय विशेष के डॉक्टरों की संख्या अधिक है। इसलिए वहां उपचार के लिए हिंदू परिवार जाने से कतराते हैं। ऐसे में जरूरत है कि अलीगढ़ में ही मौजूद दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय को एम्स की तरह विकसित किया जाए। ऐसा होने पर अलीगढ़ के साथ–साथ हाथरस, एटा, कासगंज व बुलंदशहर तक के लोगों को फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि बेशक यह बड़ा विश्वविद्यालय है, मगर एक समुदाय के कारण और कांग्रेस के एक मंत्री द्वारा एक समुदाय के लिए लिखे गए पत्र के कारण अन्य को फायदा नहीं मिल पा रहा है। बेशक वह केंद्रशासित विश्वविद्यालय है। मगर जरूरत दीनदयाल अस्पताल को एम्स की तरह विकसित करने की है। ताकि अन्य लोगों को लाभ मिल सके। सांसद का जेएन मेडिकल कॉलेज में हिंदू मरीज जाने से कतराते हैं संबंधी बयान मुनासिब नहीं है। उनके बयान से सहमत नहीं हूं। यहां पर सभी धर्मों के मरीज आते हैं। वर्ष 1992 में ढांचा विध्वंस के बाद कुछ वर्षों तक हिंदू मरीज यहां इलाज कराने से कतराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना छह हजार मरीज इलाज के लिए पर्चा बनवाते हैं।–प्रो. वीणा माहेश्वरी सीएमएस/प्राचार्या, जेएन मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, एएमयू। मरीज का नाम नहीं, बल्कि उसकी बीमारी पूछकर डॉक्टर इलाज करता है। मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ के आसपास के 12 जिलों के मरीज इलाज कराने आते हैं। इनमें सभी धर्मों के मरीज होते हैं। सांसद अगर संसद में मेडिकल कॉलेज का बजट 25 करोड़ से ज्यादा करने की बात करते तो बेहतर होता, क्योंकि यह कॉलेज उनके संसदीय क्षेत्र में आता है।–डॉ. ओबैद अहमद सिद्दीकी, सचिव, एएमयू शिक्षक संघ, एएमयू।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह विवाद

हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका

प्रयागराज,संवाददाता। भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान व शाही मस्जिद ईदगाह पक्षों के मध्य लंबित वाद में हाईकोर्ट ने वाद की पोषणियता मामले में मंदिर पक्ष में फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही है। हाईकोर्ट में 12 अगस्त से सिविल वादों की सुनवाई शुरू होगी।

मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि– शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सिविल वाद पोषणीय है। झटके पर झटका खा रही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी सिविल वादों की पोषणीयता को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन अदालत ने दिन प्रतिदिन लंबी सुनवाई की थी।

इसके बाद जून में फैसला सुरक्षित कर लिया था।

हिंदू पक्ष के सिविल वाद शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया है। इसलिए उस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। वहीं, वादियों की विधिक हैसियत पर सवाल खड़ा करते हुए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के बीच कोई विवाद नही है।

मंदिर के पक्ष में आया फैसला

विवाद खड़ा करने वाले पक्षकारों का जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी से कोई रिश्ता, वास्ता और सरोकार नहीं हैं। इसके अलावा यह भी तर्क दिया है कि ईदगाह स्थल वक्फ की संपत्ति है। 15 अगस्त 1947 को यह मस्जिद कायम थी। पूजा का अधिकार अधिनियम के तहत अब धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। बरहाल, महीनों चली लंबी बहस के बाद गुरुवार को फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को तगड़ा झटका दिया है।

हिन्दू पक्षकारों की दलील

' ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ एरिया श्रीकृष्ण विराजमान का गर्भगृह है।
' शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रेकॉर्ड नहीं है।
' श्रीकृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है।
' बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है।

मुस्लिम पक्षकारों की दलील

मुस्लिम पक्षकारों की दलील है कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। लिहाजा मुकदमा चलने योग्य नहीं है। उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त, 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। यानी उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती है।

63 दरोगाओं के तबादले

19 को पुलिस लाइन से थानों में भेजा
20 प्रभारियों को भी बदला

मुरादाबाद,संवाददाता। मुरादाबाद में तैनात 63 दरोगाओं के तबादले कर दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि बीस पुलिस चौकी प्रभारी के कार्यक्षेत्र भी बदल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी से तुरंत प्रभार ग्रहण करने को कहा गया है। मुरादाबाद एसएसपी सतपाल अंतिल ने मंगलवार देर रात जिले में तैनात 63 दरोगाओं के तबादले कर दिए। 19 दरोगाओं को पुलिस लाइन से थानों और चौकियों में भेजा है। 20 पुलिस चौकी के प्रभारियों का भी कार्यक्षेत्र बदला दिया। पुलिस लाइन से दरोगा सीताराम को रिट सेल, राजेंद्र कुमार को छजलैट, शरद कुमार को डिलारी, सुभाष कुमार सिंह को सिविल लाइंस, शांति स्वरूप को कुंदरकी प्रभारी बनाया गया है

कल्याण सिंह को मझोला, एसएसआई महेश पाल सिंह को थाना छजलैट, सलाउद्दीन को नागफनी, दीपक कुमार को कुंदरकी, संजीव कुमार, रवींद्र सिंह भाटी को मूंढापांडे, मुकेश कुमार को मूंढापांडे, देवेंद्र उपाध्यक्ष को मैनाठेर, शेरपाल, दुलीचंद, प्रदीप कुमार को कुंदरकी, अशोक कुमार को मैनाठेर, अखिल कुमार को डिलारी की जलालपुर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। कस्बा बिलारी चौकी से नीतेश सहरावत को चौकी दांग, दस सराय चौकी से देवेंद्र सिंह को फकीरपुरा चौकी प्रभारी, महिला दारोगा रीता तेवतिया को चौकी इंचार्ज फैजगंज, अंकुर सिंह को चौकी फैजगंज से थाना मैनाठेर, सोमपाल सिंह चौकी इंचार्ज मकबरा को काशीपुर तिराहा चौकी, चौकी इंचार्ज काशीपुरा तिराहा ओम शुक्ला को चौकी इंचार्ज लालबाग की जिम्मेदारी दी है।

लालबाग चौकी से नरेंद्र सिंह को जयंतीपुर, जयंतीपुर से पवन कुमार को आशियाना चौकी का प्रभारी बनाया है। आशियाना चौकी से कृष्ण कुमार को हटाकर कटघर थाने में भेजा है। पीतल बस्ती चौकी इंचार्ज हरेंद्र सिंह को हरथला चौकी इंचार्ज, प्रबोध कुमार को हरथला चौकी से पीतलबस्ती चौकी इंचार्ज, हरेंद्र सिंह को चौकी तहसील स्कूल से थाना कुंदरकी भेजा गया है। विवेक यादव को साइबर थाने से चौकी इंचार्ज तहसील स्कूल, प्रवेंद्र कुमार को मझोला थाने से चौकी कांशीरामनगर, उचित कुमार सिंह को चौकी गुलाबबाड़ी से पुलिस लाइन, सौरभ त्यागी को पुलिस लाइन से गुलाबबाड़ी, पुलिस लाइन से अर्जुन सिंह को टीपी नगर चौकी इंचार्ज, टीपी नगर चौकी इंचार्ज सुशील चौधरी को चौकी इंचार्ज खदाना बनाया गया है। हरेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से मकबरा, मनोज पवार को चौकी लाइनपार से थाना मैनाठेर, सर्वेश कुमार को पुलिस लाइन से लाइनपार चौकी, ओमपाल सिंह को कांशीराम नगर से थाना डिलारी, सुरेंद्र सिंह चौकी इंचार्ज रौंडा झोंडा से मैनाठेर, देव सिंह को चौकी इंचार्ज रानी नांगल से पुलिस लाइन, नीरजपाल सिंह को थाना डिलारी से पुलिस लाइन भेजा गया है।

रमेश गिरी को चुनाव सेल रानी नांगल, सविता तोमर को पुलिस लाइन से कोतवाली, हंसराज को पुलिस लाइन से मूंढापांडे, बबलू को मूंढापांडे से मैनाठेर, रामभूल सिंह को भगतपुर से कुंदरकी भेजा गया है। उदयवीर सिंह मुगलपुरा से मूंढापांडे, महेश चंद गुप्ता को पुलिस लाइन से मूंढापांडे, नरेश कुमार राठी को यूपी 112 से मूंढापांडे भेजा गया है। स्वाति राणा को पुलिस लाइन से साइबर थाना, जयशंकर द्विवेदी को पुलिस लाइंस से पाकबड़ा, हेमंत कुमार मूंढापांडे से कटघर, सलीम मलिक कुंदरकी से नागफनी, देवेंद्र सिंह कोतवाली से पुलिस लाइंस, वंदना रस्तोगी को महिला थाना से पुलिस लाइन, रामगोपाल आर्य को गलशहीद से सिविल लाइंस थाने में तैनाती दी है।

भानवी सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट

'मुख्यमंत्री मेरे साथ भी इंसाफ करें दबाव में काम कर रही पुलिस'

प्रतापगढ़,संवाददाता। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री से इंसाफ मांगा है। उन्होंने कहा कि पुलिस दबाव में कार्य कर रही है। इसके पहले भानवी सिंह गृहमंत्री अमित शाह को एक्स पर पोस्ट करके न्याय की गुहार लगा चुकी हैं।

जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा उर्फ भैया की पत्नी भानवी सिंह ने बृहस्पतिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से इंसाफ मांगा है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में आपका महिला सुरक्षा पर दिया गया भरोसा अच्छा लगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक महिला हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी उस फरियाद पर भी आप ध्यान देंगे, जिसे मैंने बार–बार यूपी सरकार और यूपी पुलिस के सामने रखा।मेरा आपसे अनुरोध है ।

हजरतगंज कोतवाली में मेरे खिलाफ फर्जी मकदमे पर एक्शन लीजिए। जिसमें मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। मेरी मानसिक प्रताड़ना और मुझे तोड़ने के लिए एक कोतवाली और वहां के चंद पुलिस अफसरों का इस्तेमाल बंद करवाइए। मेरी शिकायत पर भी केस दर्ज करने का आदेश दें। सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिसकर्मी किसके दबाव में काम कर रहे है? इसकी जांच करवाइए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश देकर न्याय करेंगे।

जापान जाएंगी यूपी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बेटियां

लखनऊ [redacted] उत्तर प्रदेश की कस्तूरवा गांधी आवासीय वालिका विद्यालय में अध्ययनरत दो वालिकाओं को जापान के सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में प्रतिभाग करने का मौका मिला है। ये वेटियां क्रमशः प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिलों की रहने वाली है। विज्ञान के योग्य शिक्षकों के सुपरविजन में जापान जाने वाली वालिकाओं को अन्य देशों के वच्चों व विशेषज्ञों के साथ शैक्षिक नवाचार के अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलेगा।

- जापान के सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में प्रतिभाग करेंगी संध्या और रिया
- योगी सरकार में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है लाभ

जापान साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एजेंसी द्वारा सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम पहली अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जापान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उप्रकी दो वालिकायें कुमारी संध्या सरोज (कस्तूरवा गांधी वालिका विद्यालय वहरिया, प्रयागराज) और कुमारी रिया पटेल (कस्तूरवा गांधी वालिका विद्यालय, सदवा चंद्रिका, प्रतापगढ़) का चयन हुआ है। 10 नवम्वर से 16 नवंवर के वीच होने वाले सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में प्रतिभाग करने का इन्हें मौका मिला है।

इन्हें मिलता है अवसर : ज्ञातव्य हो कि सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम ऐसे वच्चों के लिये आयोजित किया जाता है, जो विज्ञान वर्ग में 11वीं व 12वीं के छात्र हों और कक्षा 10 के टॉपर हों। इनमें अंग्रेजी वोलने की दक्षता का होना भी आवश्यक है। ऐसे में इन दोंनों वालिकाओं का चयन यह वताता है कि योगी सरकार में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदेश की वेटियों को लाभ मिल रहा है।

जापान उठाएगा खर्च : वालिकाओं पर आने वाला सारा खर्च जापान विज्ञान व प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) द्वारा वहन किया जायेगा। चाहे वह जापान भ्रमण पर आने वाला खर्च हो अथवा इनके रहने एवं खाने-पीने पर होने वाला व्यय हो; सारा खर्च जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) करेगी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को जापान सरकार द्वारा भ्रमण अवधि का वीजा भी उपलब्ध कराया जायेगा।

नोबल पुरस्कार विजेताओं से मिलने का भी मौका : सकूरा साइंस हाईस्कूल प्रोग्राम में शामिल होने वाले वच्चों को नोवेल पुरस्कार विजेताओं से भी मिलाया जाता है। प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विशेष विषयों में भागीदारी, प्रमुख जापानी विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों का भ्रमण कराकर इनके ज्ञान और अनुभावों को अत्यधिक पुष्ट किया जाता है। इन्हें जापानी हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करने का अवसर दिलाकर जापानी संस्कृति का अनुभव भी कराया जाता है। जापान विज्ञान प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) जापान व अन्य देशों के युवाओं के वीच शैक्षिक नवाचार में अनुभवों का आदान-प्रदान वढ़ाने के उद्देश्य से जापान साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम को लागू किया गया है। इसे सकूरा साइंस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। सकूरा साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत जेएसटी द्वारा उत्कृष्ट श्रेणी के हाई स्कूल छात्र-छात्राओं को एक सप्ताह के लिए आमंत्रित किया जाता है।

एक करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों से पुलिस को मिले अहम सुराग

लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने गिरोह के चार जालसाजों को घैलापुल के पास से गुरुवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस को पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में दबिश दे रही है। कई लोगों के नंबर भी सूवलांस पर ले लिए गए हैं। मोबाइल में पुलिस को कई नंबर मिले हैं और गिरोह के बारे में कई अहम राज पता चले हैं।

संवाददाता, लखनऊ।

डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से एक करोड़ से अधिक की रकम ठगने वाले गिरोह के चार सदस्यों से ठाकुरगंज पुलिस को पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में दबिश दे रही है। कई लोगों के नंबर भी सर्विलांस पर ले लिए गए हैं। ठाकुरगंज पुलिस ने इस गिरोह के चार जालसाजों को घैलापुल के पास से गुरुवार को गिरफ्तार किया था। इनके पास से तीन मोबाइल, तीन फर्जी आधार कार्ड, तीन पैनकार्ड व एक एटीएम बरामद किया है। मोबाइल में पुलिस को कई नंबर मिले हैं और गिरोह के बारे में कई अहम राज पता चले हैं।

टेलीग्राम पर ललक भेजकर रकम दोगुनी करने की भी देते थे लालच

गिरफ्तार आरोपितों में मड़ियांव के डिडौली निवासी अभिषेक शुक्ला, फैजुल्लागंज निवासी दिव्यांश श्रीवास्तव, डिडौली निवासी अभिषेक कुमार रावत और केशवनगर का अरविंद कश्यप है। जालसाजों ने पुलिस को बताया था कि वह लोगों को टेलीग्राम पर लिंक भेज कर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराते थे। लोगों को बातों में फंसाकर विश्वास में लेते थे।

कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर निवेश कराते थे। फिर लोगों के उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज मांग कर फर्जी बैंक खाते खुलवाते थे। मोटी रकम निवेश होने पर वे खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। वहीं जो लोग उनके जाल में नहीं फंसते थे तो उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लेते थे। इसी तरह से उन्होंने जयपुर निवासी भूपेंद्र चौहान, राजस्थान के निवासी सतीश कुमार, महाराष्ट्र के चैतन्य कुलकर्णी व आनंद वसंत से करीब एक करोड़ रुपए ऐंठे थे।

बरतें विशेष सावधानियां

एसीपी साइबर क्राइम अभिनव के मुताबिक, दुनिया में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। जालसाजों ने कुछ माह से ठगी का तरीका बदल दिया है। ऐसे में हमे सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, तभी हम ठगी से बच सकते हैं। लोगों के विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

दुनिया में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है।

पुलिस कभी वाट्सऐप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम पर वीडियो कॉल करके अरेस्ट नहीं करती है।

पुलिस जब भी किसी को फोन काल करती है मैनुअल करती है।

अनजान नंबर से वीडियो कॉल रिसीव न करें।

ऐसे पहचाने इन जालसाजों के नंबर

यह हमेशा वीडियो कॉल करते हैं।

इनके नंबर पाकिस्तान, अफानिस्तान, दुबई विदेशी नंबर जैसे होते हैं।वा इंटरनेट कॉलिंग के नंबर होते हैं।

वायनाड में राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा

केरल : लोकसभा में विपक्ष के नेता व वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड के चूरलमाला में भूस्खलन स्थल पर पहुंचे।

हिमाचल में बादल फटने से हाहाकार, रेस्क्यू टीम ने सात लोगों को बचाया, सरकार ने हेल्पलाइन नंबर किए जारी

केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मेप्पाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अबतक 173 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 219 घायल हैं। यह आंकड़ा अभी और भी अधिक बढ़ सकता है। वहीं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सेना का राहत व बचाव कार्य जारी है।

छुट्टा पशु को लेकर खूनी संघर्ष

लखीमपुर खीरी में दो ग्रामीणों की पीट-पीटकर हत्या, छह लोग घायल

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले के भीरा थाना क्षेत्र में छुट्टा पशु को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खेत से भगाने पर छुट्टा पशु एक घर में घुस गया, जिससे नाराज दबंगों ने दो ग्रामीणों की पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है।

लखीमपुर खीरी जिले में सनसनीखेज वारदात हुई है। भीरा थाना क्षेत्र के देवरिया रणा गांव में शुक्रवार की रात घर में छुट्टा जानवर घुसने से नाराज दबंगों ने दो युवकों की पीट- पीटकर हत्या कर दी। घटना में छह से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि युवकों ने लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ा था।

गांव रणा निवासी रामजीत पुत्र जसवंत पक्ष के खेतों में शुक्रवार शाम छुट्टा जानवर घुस गए थे। भगाने पर जानवर दूसरे पक्ष के संतराम के घर में घुस गए। इस पर संतराम और उनके पक्ष के लोगों ने रामजीत के लड़कों को पीट दिया। पता चला तो रामजीत के घरवाले शिकायत करने पहुंचे।

गांव में देर रात हुआ बवाल

इससे बौखलाए संतराम और उसके पक्ष के लोगों ने शिकायत करने आए लोगों पर हमला कर दिया। लाठी-डंडे लेकर रामजीत के घर में घुस गए। देर रात दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट में रामजीत, उनके पक्ष के रामलखन उर्फ गुड्डू और करीब सात लोग घायल हुए।

सभी को जिला अस्पताल लाया गया। जहां से रामजीत और गुड्डू को लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। विनीत, कौशलेंद्र, रामदेव आदि घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव में तनाव का माहौल है। कई थानों की पुलिस गांव में तैनात है।

एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फायदा किसे

दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य एससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण का फैसला सुनाया है। इस फैसले की देशभर में चर्चा हो रही है। सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से सुनाए ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति दे दी है। इससे अब तक पूरी तरह हाशिये पर रहे समूहों को व्यापक फायदा मिलेगा। 2004 में भी शीर्ष अदालत ने माना था कि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब इस फैसले पर देश के तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोजपा (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले का पुर्नविचार किया जाए। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे 'ऐतिहासिक' करार दिया। आइये जानते हैं कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण का पूरा मामला क्या है? इसके पुनरीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे हुई मामले की शुरुआत? इस फैसले से किसे फायदा मिलेगा?

पहले जानते हैं कि अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण क्या है?

अदालत के सामने राज्यों ने तर्क दिया है कि अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है। अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में भी सामने आई है और इसे मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। 2007 में, बिहार ने अनुसूचित जातियों के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया।

तमिलनाडु में अनुसूचित जाति कोटे के अंतर्गत अरुंधतियार जाति को तीन प्रतिशत कोटा दिया गया है, क्योंकि न्यायमूर्ति एम.एस. जनार्थनम की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16 होने के बावजूद उनके पास केवल 0-5 नौकरियां हैं। 2000 में, आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने 57 अनुसूचित जातियों को उप-समूहों में पुनर्गठित करने और शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 15 अनुसूचित जाति कोटा को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटने का कानून पारित किया। हालांकि, इस कानून को वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का पूरा मामला क्या है?

उच्चतम न्यायालय के सात न्यायधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इसमें कहा गया कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब है कि राज्य एससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया है। इसके जरिए 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए पांच जजों के फैसले को पलट दिया। बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि एससी/एसटी में उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।

इस मामले की सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल रहे। पीठ ने इस मामले पर तीन दिनों तक सुनवाई की थी और बाद 8 फरवरी, 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की थी। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले को 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में पांच जजों वाली पीठ ने सात जजों वाली पीठ को सौंप दिया था। पांच जजों वाली पीठ ने पाया कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से प्रतिनिधित्व किए गए राज्यों ने ईवी चिन्नैया मामले में फैसले की समीक्षा की मांग की थी। साल 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उप-वर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है।

अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है और इसका असर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोटा के लिए एससी में उप-वर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों और आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। वहीं, न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अलग दिए फैसले में कहा कि राज्यों को एससी, एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। बता दें कि चार न्यायाधीशों ने अपने-अपने फैसले लिखे जबकि न्यायमूर्ति गवई ने अलग फैसला दिया। ताजा फैसला उन राज्यों के लिए बेहद अहम साबित होगा जो प्रमुख अनुसूचित जातियों की तुलना में आरक्षण के बावजूद सीमित प्रतिनिधित्व वाली कुछ अन्य जातियों को आरक्षण का व्यापक लाभ देना चाहते हैं। कोर्ट के इस तथ्य पर मुहर लगाई है कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हो सकतीं।

अब फैसले से राज्यों को आरक्षण पर अपने हिसाब से कानून बनाने का मौका मिल सकेगा। उप-वर्गीकरण रणनीति का पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिखों, आंध्र प्रदेश में मडिगा के अलावा बिहार में पासवान, यूपी में जाटव और तमिलनाडु में अरुंधतियार समुदाय पर सीधा असर पड़ेगा।

धर्मेंद्र के लिए जन्नत जुबैर ने पकाए फुल्के और मेथी मलाई मटर, एक्टर ने जमकर की तारीफ

मुम्बई। एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने उस 'भावुक' पलों को याद किया है, जब दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' के नए एपिसोड में उनके पकाए स्वादिष्ट पंजाबी व्यंजन की तारीफ की थी। अतिथि के रूप में शो में आए धर्मेन्द्र के लिए लाफ्टर शेफ्स ने एक नई चुनौती लेते हुए पंजाबी भोजन तैयार किया। मेनू में मक्के की रोटी, साग, फुल्का, पंजाबी कढ़ी पकौड़ा, चावल और मेथी मलाई मटर शामिल थे। इससे पहले कभी भी जन्नत और रीम शेख ने मेथी मलाई मटर और फुल्का नहीं पकाया था, मगर फिर भी उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की। धर्मेंद्र ने उनके प्रयास और मेहनत की जमकर तारीख की। उन्हें व्यंजन इतने पसंद आए कि उन्होंने घर ले जाने के लिए कुछ पैक करवाने का अनुरोध किया।

इस बारे में बात करते हुए जन्नत ने कहा, "फुल्का और मेथी मलाई मटर पकाना रोमांचक और नर्वस करने वाला दोनों था। मैंने पहले कभी इस व्यंजन को नहीं चखा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि इसका स्वाद कैसा होना चाहिए।" उन्होंने बताया, "रीम और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, खासकर यह जानते हुए कि धर्मेन्द्र सर इसे चखेंगे। हमारा ध्यान टास्क जीतने या हारने से हटकर केवल इस बात पर था कि यह स्वादिष्ट बने। सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना था कि स्वाद सही है या नहीं।"जन्नत ने कहा, ''जब धर्मेन्द्र सर ने इसे चखा और इसे इतना पसंद किया कि कहा वो इसे घर ले जाना चाहते हैं, यह मेरे लिए एक अविश्वसनीय रूप से भावुक क्षण था। हमारी सारी मेहनत की सराहना की गई, और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"

आदर जैन से ब्रेकअप के बाद अरुणोदय सिंह को डेट कर रही हैं

तारा सुतारिया!

पूर्व शिक्षा मंत्री के पोते हैं एक्टर

खबर है कि आदर जैन से ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया, अरुणोदय सिंह को डेट कर रही हैं। अरुणोदय सिंह का 2019 में पत्नी से तलाक हो गया था और तारा का भी ब्रेकअप हो गया था। रिपोर्ट्स हैं कि तारा सुतारिया और अरुणोदय सिंह पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में हैं।

खबर है कि आदर जैन से ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया, अरुणोदय लसह को डेट कर रही हैं अरुणोदय सिंह का 2019 में पत्नी से तलाक हो गया था और तारा का भी ब्रेकअप हो गया था
रिपोर्ट्स हैं कि तारा सुतारिया और अरुणोदय लसह पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में हैं

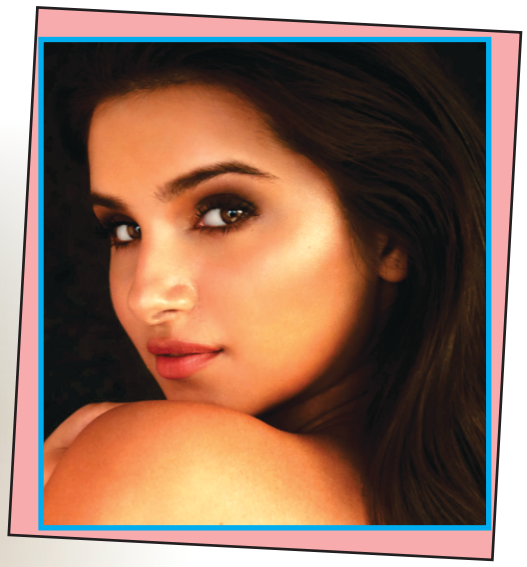

ऐसा लगता है कि आदर जैन से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस तारा सुतारिया को अपना हमसफर मिल गया है। खबर है कि वह एक्टर अरुणोदय सिंह को डेट कर रही हैं। दोनों के बीच केमिस्ट्री दोस्ती से भी ज्यादा बढ़कर है। मालूम हो कि अरुणोदय सिंह तलाकशुदा हैं। उन्होंने 2016 में ली एन एल्टन से शादी की थी, पर 2019 में उनका तलाक हो गया था। वहीं, तारा सुतारिया और आदर जैन ने साल 2022–23 में अपना रिश्ता खत्म कर दिया था।

हमारे सहयोगी 'ईटाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक,डेढ़ साल से एक–दूसरे को डेट कर रहे हैं। तारा के पैरेंट्स भी अरुणोदय को काफी पसंद करते हैं, और दोनों अकसर डेट्स पर जाते नजर आए हैं। अरुणोदय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री (मानव संसाधन मंत्री) रहे अर्जुन सिंह के पोते हैं।

ऐसे शुरू हुआ तारा सुतारिया और अरुणोदय सिंह का रिश्ता

एक सोर्स ने बताया, 'तारा सुतारिया और अरुणोदय सिंह का रिश्ता एक–जैसी पसंद और सोच से शुरू हुआ। दोनों को आर्ट काफी पसंद है। दोनों साथ में काफी वक्त बिता रहे हैं। तारा की फैमिली न सिर्फ अरुणोदय सिंह के बारे में जानती है, बल्कि उन्हें पसंद भी करती है। दोनों डेट्स पर भी जाते हैं। बस उन्होंने अपने अफेयर के बारे में सबको बताने के लिए पीआर नहीं रखा है। तारा सुतारिया अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहती हैं और अरुणोदय भी बेहद प्राइवेट इंसान हैं।'

तारा के पैरेंट्स को पसंद हैं अरुणोदय सिंह

सोर्स ने आगे बताया कि तारा सुतारिया और अरुणोदय सिंह बिल्कुल एक–जैसे हैं। उनकी पसंद–नापसंद भी काफी मिलती है। दोनों को तारा सुतारिया के पैरेंट्स के साथ बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में डेट पर भी स्पॉट किया गया था। तारा पहले आदर जैन को डेट कर रही थीं और उन्होंने साल 2020 में अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था, पर यह रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला।

12वीं फेल में नजर आ चुकी हैं मेधा शंकर
दर्शकों ने एक्ट्रेस के किरदार को किया था काफी पसंद
1 अगस्त को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं मेधा

'12वीं फेल'

श्रद्धा जोशी' के किरदार से अलग होने में लगा समय

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12वीं फेल बीते साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में विक्रांत मैसी और मेधा शंकर ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म की कहानी के साथ–साथ स्टार्स की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया। लोगों ने मेधा को नेशनल क्रश का टैग दे दिया था। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी मूवी और पर्सनल लाइफ को लेकर बात की है।

दिमाग में बसा ली श्रद्धा की छवि

एक्ट्रेस मेधा शंकर आज 1 अगस्त को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने एचटी के साथ बात करते हुए बताया कि वह इस खास दिन पर अपने खास फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ अलीबाग जाने का प्लान बना रही हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि यह मेरे लिए खास जन्मदिन है। हमने एक विला बुक किया है, जहां हम टेबल टेनिस, बैडमिंटन खेलेंगे। साथ ही टेस्टी फूड भी एन्जॉय करेंगे। हम इसे मुंबई के आसपास इसलिए मना रहे हैं, ताकि हम अपने डॉग लैला को साथ ले जा सकें। वहीं, उन्होंने 12वीं फेल में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। लोगों को मेरा किरदार इतना पसंद आया कि उन्होंने श्रद्धा जोशी के रूप में मेरी छवि अपने दिमाग में बसा ली।

किरदार से अलग होने में लगा समय

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्हें श्रद्धा के किरदार से हटकर, जो वह हैं उसमें खुद को ढालने में समय लगा। साथ ही जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वह ब्रेक पर हैं। इसके बारे में बात करते हुए मेधा ने कहा कि उनके पास कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन वह स्क्रिप्ट को लेकर काफी चयनात्मक हैं। मेधा ने कहा कि मैं सच में खुद को उन कहानियों के साथ चुनौती देना चाहती हूं, जिन्हें मैं चुन रही हूं। मैं अपनी पिछली छवि को तोड़ना चाहती हूं, ताकि अगली फिल्म में मैं ऐसी भूमिका निभा सकूं, जो अब तक मैंने निभाई है उससे बहुत अलग हो।

साथ ही मैं हमेशा से ही दमदार भूमिकाएं निभाना चाहती हूं, जहां लड़की के किरदार के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो। फिर कुछ निर्देशक भी हैं, जिनके साथ मैं वास्तव में काम करना चाहती हूं।

नेशनल अवॉर्ड पर क्या बोलीं मेधा

12वीं फेल के नेशनल अवॉर्ड की दौड़ में शामिल होने की चर्चा से ही मेधा शंकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इतने सारे लोग हमारे लिए उत्साहित हैं। हम जीतें या न जीते, हमें फिल्म और हमारे अभिनय के लिए जो प्यार मिला है, वह सब कुछ है जो मैं चाहती थी।

विक्रांत मैसी के साथ 12वीं फेल में नजर आ चुकी एक्ट्रेस मेधा शंकर आज 1 अगस्त को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास दिन पर उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कई चीजें एक इंटरव्यू में शेयर की हैं। इसके साथ ही मेधा शंकर ने बताया है कि वह कैसे अपने इस खास दिन को सेलिब्रेट करने वाली हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपना 32वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी दमदार एक्टिंग से एक्ट्रेस इंडस्ट्री में राज कर रही हैं। अब भले ही सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनकी शादी हो गई है लेकिन इससे कियारा का कई एक्टर्स के साथ नाम जुड़ चुका है।

वरुण धवन संग भी जुड़ा था नाम

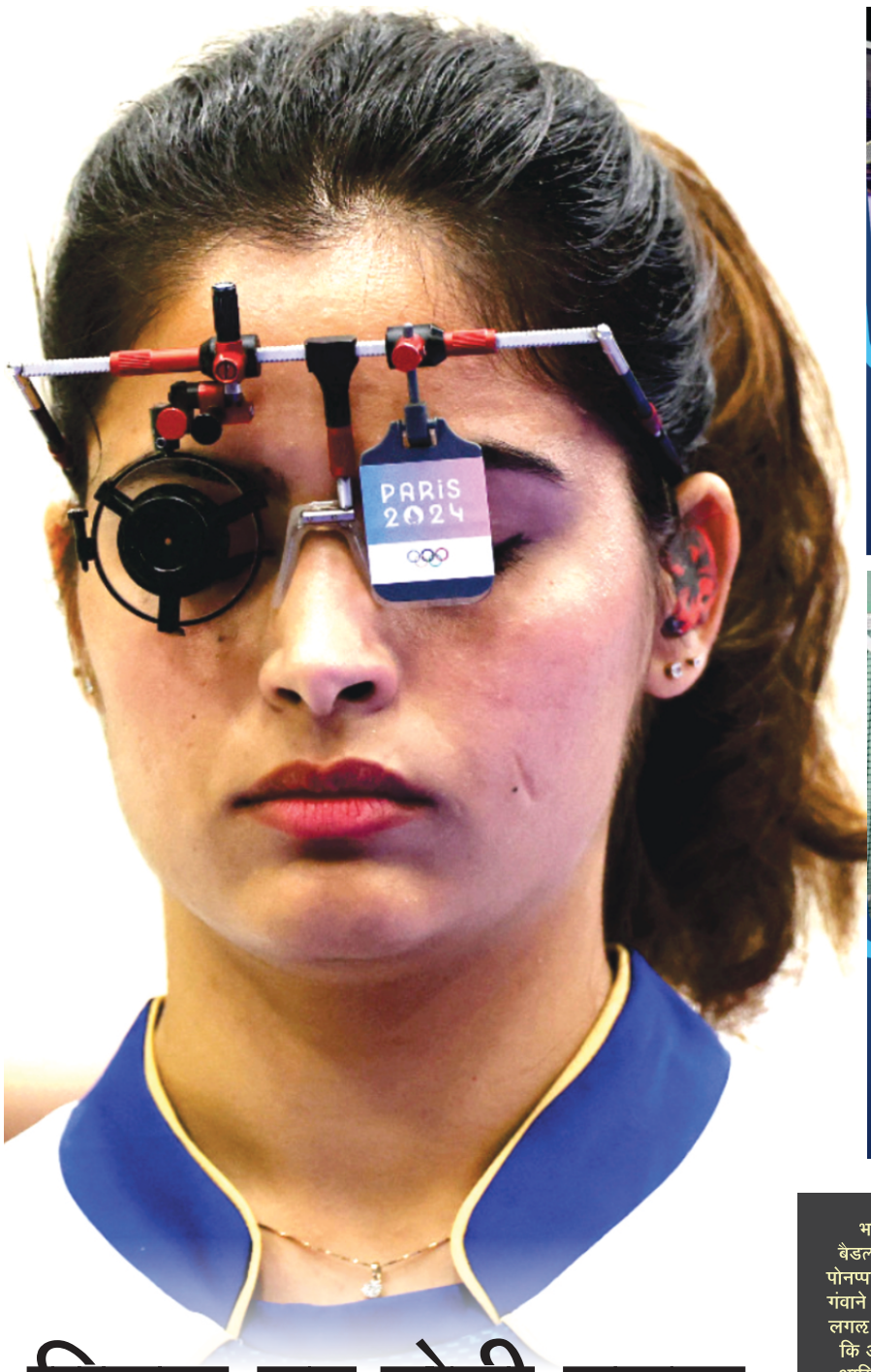

पिनल पर होगी पदक दिलाने की जिम्मेदारी

OLYMPIC BREAKING

पीवी सिंधु ने राउंड ऑफ 16 में किया क्वालीफाई

OLYMPIC BREAKING

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराया

OLYMPIC BREAKING

पीवी सिंधु के बाद लक्ष्य सेन प्री-क्वार्टर फाइनल में..

भारत की स्टार महिला बैडलमटन खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा पेरिस ओलंपिक्स में मैच गंवाने के बाद फूट–फूटकर रोने लगल। अश्विनी पोनप्पा ने कहा कि ओलंपिक्स में यह उनका आखिरी मैच था। पोनप्पा को करियर में ओलंपिक मेडल पाने का मलाल जरूर रहेगा। पेरिस ओलंपिक्स में अश्विनी पोनप्पा ने तनिशा क्रास्तो के साथ जोड़ी बनाई थी लेकिन यह जोड़ी एक भी मैच नहल जीत पाई ।

अश्विनी पोनप्पा पेरिस ओलंपिक्स में मैच हारने के बाद फूट–फूटकर रोईं, 34 साल की पोनप्पा ने कहा कि यह ओलंपिक्स उनका आखिरी था, तनिशा क्रास्तो के साथ अश्विनी पोनप्पा पेरिस ओलंपक्सि में एक भी मैच नहीं जीत सकी।

अश्विनी पोनप्पा का पेरिस ओलंपिक से बाहर होते ही बड़ा ऐलान, कहा - मैंने अपना आखिरी ओलंपिक खेल लिया

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बाहर होने के बाद फूट–फूटकर रोने लगीं। 34 साल की पोनप्पा ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स उनका आखिरी था। अश्विनी ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए तनिशा क्रास्तो के साथ जोड़ी बनाई थी। हालांकि, भारतीय महिला डबल्स जोड़ी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वो लगातार तीन मैच हारकर ग्रुप चरण से बाहर हो गई। अश्विनी–तनिशा को अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी सेतयाना मपासा व एंजेला यू के हाथों 15–21, 10–21 से शिकस्त सहनी पड़ी। इसी के साथ अश्विनी–तनिशा का पेरिस ओलंपिक्स में अभियान समाप्त हो गया।

अश्विनी पोनप्पा का भावुक बयान

यह पूछने पर कि 2028 लॉस एंजिलिस गेम्स में खेलने की उम्मीद रखती हैं तो पोनप्पा ने कहा, ''यह मेरा आखिरी ओलंपिक्स था, लेकिन तनिशा को काफी आगे तक जाना है। भावुक और मानसिक रूप से काफी बल पड़ता है। मैं दोबारा इस चीज से नहीं गुजर सकती हूं। यह आसान नहीं है। अगर आप थोड़े जवान होते तो इस दबाव को झेल सकते थे। इतने लंबे समय तक खेलने के बाद मैं और दबाव नहीं झेल सकती।''

ओलंपिक में आज भारत के मुकाबले

पेरिस ओलंपिक 2024

- 11:00 AM — पुरुष 20 मीटर पैदल चाल में परमजीत सिंह बिष्ट, आकाशदीप सिंह, विकास सिंह चुनौती पेश करेंगे
- 12:30 PM — गोल्फ में शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर चुनौती पेश करेंगे
- 12:50 PM — महिला 20 मीटर पैदल चाल में प्रियंका एक्शन में होंगी
- 01:00 PM — पुरुषों के 50 मी. राइफल 3 पोजीशन फाइनल में स्वप्नि कुसाले पेश करेंगे चुनौती
- 01:30 PM — हॉकी में भारत-बेल्जियम मैच
- 2:30 PM — बॉक्सिंग में निकहत एक्शन में होंगी
- 2:3? PM — पुरुष तीरंदाजी में प्रवीण जाधव एक्शन में होंगे
- 3:30 PM — अंजुम मोदगिल, सिफ्त कौर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबले में उतरेंगी
- 3:45 PM — नौकायन में विष्णु सर्वानन चुनौती पेश करेंगे
- 7:05 PM — महिला नौकायन में कुमनन नेत्रा चुनौती पेश करेंगी

स्पोर्ट्स डेस्क। पेरिस ओलंपिक में गोल्फ स्पर्धा की शुरुआत गुरुवार से होगी। पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोल प्ले राउंड–1 में गगनजीत भुल्लर और शुभंकर शर्मा भारत की ओर से चुनौती पेश करने उतरेंगे।

भारतीय दल के लिए पेरिस ओलंपिक खेलों का पांचवां दिन अच्छा रहा। बुधवार को भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुरुवार को उनसे भारत को तीसरा पदक दिलाने की आस रहेगी। वहीं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पूल बी में बेल्जियम से होगा। मुक्केबाजी में निकहत जरीन महिला 50 किग्रा वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में चुनौती पेश करेंगी।

गोल्फ स्पर्धा का होगा आगाज

पेरिस ओलंपिक में गोल्फ स्पर्धा की शुरुआत गुरुवार से होगी। पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोल प्ले राउंड–1 में गगनजीत भुल्लर और शुभंकर शर्मा भारत की ओर से चुनौती पेश करने उतरेंगे। वहीं, तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में प्रवीण जाधव चीन के काओ वेनचाओ के खिलाफ उतरेंगे। वहीं, एथलेटिक्स की स्पर्धाओं की भी शुरुआत छठे दिन से होने जा रही है जिसमें पुरुष 20 मीटर पैदल चाल में तीन भारतीय उतरेंगे, जबकि महिलाओं के 20 मीटर पैदल चाल में प्रियंका चुनौती पेश करेंगी।

ओलंपिक के लिए बर्फ पर चले और घास पर सोई भारतीय हाकी टीम

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और ऐसा लगता है कि स्विट्जरलैंड के बूट कैंप का फायदा मिलेगा। होर्न एक साहसिक और खोजकर्ता के रूप में विख्यात हैं। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला आल्पस की सबसे ऊंची चोटी ग्लेशियर 3000 पर चलने से लेकर लुभावनी रूजमोंट में साइकिल चलाने और घास पर सोने तक भारतीय हॉकी टीम ने मिशन पेरिस ओलंपिक के लिए कड़ा अभ्यास किया है। स्विट्जरलैंड के लाइफ कोच 58 साल के माइक होर्न ने टीम में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने और असफलता का डर निकालने के लिए तीन दिन के बूट कैंप में कड़ी मेहनत कराई है। होर्न एक साहसिक और खोजकर्ता के रूप में विख्यात हैं और उन्होंने 2011 में विश्वकप विजेता बनी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, आईपीएल टीम केकेआर और 2014 विश्व कप फुटबॉल चैंपियन जर्मन टीम के साथ काम किया है। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय हॉकी टीम ने स्विट्जरलैंड में शिविर में हिस्सा लिया तो सभी को अपेक्षा थी कि टीम ओलिंपक से पहले जरूरी मानसिक दृढ़ता हासिल कर लेगी।

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार
मो0. नं0. 7307180148,9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद–विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।